Drishti IAS

करेंट अफेयर्स छत्तीसगढ़

सितम्बर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब मिलेगा 4 प्रतिशत बढ़ा महँगाई भत्ता 3
- वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल 3
- 52 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान से होंगे सम्मानित 4
- राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार-2023 की घोषणा 5
- स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 8
- जी-20 में आईं फर्स्ट लेडी को बस्तर की महिलाओं की ओर से मिलेट का उपहार 8
- मुख्यमंत्री ने 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों को 23.93 करोड़ रुपए का किया भुगतान 9
- छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड 10
- हीरक जयंती पर मुख्यमंत्री ने रायपुर मेडिकल कॉलेज के 700 बिस्तर क्षमता वाले नए चिकित्सालय भवन का किया भूमिपूजन 11
- छत्तीसगढ़ सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला 12
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में 'कमर्शियल हब', 'एरोसिटी' और 'शहीद स्मारक'की रखी आधारशिला 14
- मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया तथा छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला रखी 15
- छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मिली मान्यता 16
- जलजीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से मिला प्रशस्ति-पत्र 17
- डेटा-एआई क्लब के गठन के लिये रायपुर ज़िला प्रशासन और आईजेब्रा-एआई के मध्य हुआ एमओयू 18
- प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं 19
- शालेय राज्य स्तरीय ताईक्वांडो में जशपुर को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 काँस्य पदक मिले 20
- संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक: बालोद बना ओवरऑल चैंपियन 21
- जैविक प्रमाणीकरण के लिये छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट संचालित 22
- मुख्यमंत्री ने ईटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण 23
- मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम, बीपीओ सेंटर और तारामंडल का किया लोकार्पण 25
- 38वें चक्रधर समारोह का हुआ गरिमामयी शुभारंभ 26
- मुख्यमंत्री 'मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस' में हुए शामिल 28
- यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सराहा 29
- छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) लगातार तीसरी बार पुरस्कृत 29
- छत्तीसगढ़ की चॉक परियोजना को विश्व बैंक एवं भारत सरकार से मंज़ूरी मिली 30
- मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ 31
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित अत्याधुनिक सेंट्रल लाईब्रेरी (ग्रंथालय) का किया लोकार्पण 32
- आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को मिले तीन पुरस्कार 33
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 34
- विधानसभा उपाध्यक्ष ने अड़ेगा रीपा में प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई का किया शुभारंभ 35
- छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी फिक्की अवॉर्ड से सम्मानित 36
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया 37
- राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन 38
- कबीरधाम ज़िले के सरोधा-दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार 38
- मुख्यमंत्री ने बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का किया लोकार्पण 40
- मुख्यमंत्री ने किया निर्भया कमांड और कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ 41
- मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नवनिर्मित 'छत्तीसगढ़ निवास' का किया वर्चुअल शुभारंभ 43
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कोटरा और हतबंध पीएचसी तथा कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र 44
- खाद्य मंत्री ने उलकिया में फूडपार्क का किया लोकार्पण 44

नोट :

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स को बड़ी राहत, अब मिलेगा 4 प्रतिशत बढ़ा महँगाई भत्ता

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप छत्तीसगढ़ के पेंशनर्स अधिकारी-कर्मचारियों का महँगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग ने इसके लिये आदेश जारी कर दिया है।

प्रमुख बिंदु

- सातवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन के लिये महँगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ इसी जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के पश्चात् अब महँगाई राहत 42 प्रतिशत हो गई है।
- इसके साथ ही छठवें वेतनमान के मूल पेंशन/परिवार पेंशन पाने वाले पेंशनर्स के महँगाई भत्ते में 9 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। यह लाभ भी इसी साल के जुलाई महीने की पहली तारीख से मिलेगा। इस वृद्धि के साथ ही महँगाई राहत में कुल वृद्धि 221 प्रतिशत हो गई है।
- उल्लेखनीय है कि पेंशनर्स की महँगाई राहत के संबंध में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों की स्वीकृति आवश्यक होती है। इस संबंध में स्वीकृति जल्द प्रदान करने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा था। इसके बाद जैसे ही स्वीकृति प्राप्त हुई, महँगाई राहत में वृद्धि का लाभ पेंशनर्स को प्रदान करने का अविलंब निर्णय लिया गया।

वन अधिकार मान्यता के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल

चर्चा में क्यों ?

3 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता अधिनियम का प्रभावी और संवेदनशीलता के साथ क्रियान्वयन हो रहा है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में आदिवासी-वनवासियों सहित गरीब तथा कमज़ोर वर्ग के समस्त लोगों को काफी राहत मिली है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई है।
- छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता-पत्र के संदर्भ में कुल 5 लाख 17 हज़ार 096 हितग्राहियों को वन अधिकार-पत्र प्रदाय किये गए हैं। व्यक्तिगत वन अधिकार-पत्र प्रदाय करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है।
- इसके अंतर्गत हितग्राहियों के समग्र विकास के लिये भूमि समतलीकरण, जल संसाधनों का विकास तथा क्लस्टर के माध्यम से हितग्राहियों को अधिकाधिक लाभ के उद्देश्य से अनेक योजनाओं के माध्यम से मदद पहुँचाई गई है।
- इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी. श्रीनिवास राव ने बताया कि हितग्राहियों को राज्य की जनहितकारी योजनाओं, जैसे- निजी भूमि पर बाईबेक गारंटी के साथ 'मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना', फसल विविधता को प्रोत्साहित करने के लिये धान के बदले अन्य रोपण हेतु प्रोत्साहन राशि का प्रावधान आदि से भी जोड़ा जा रहा है।
- इसके तहत भूमि विकास के फलस्वरूप प्रति हितग्राही कृषि उत्पादन बढ़ गया है और अनेक प्रकार की आय-मूलक फसलों (कैश क्रॉप) का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में किया जा रहा है। इसके कारण हितग्राहियों का आजीविका उन्नयन भी सुनिश्चित हुआ है। साथ ही साथ इससे वन सुरक्षा के प्रति जनता का सीधा सरोकार सामने आया है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।

नोट :

- इसी तरह राज्य में सामुदायिक वन अधिकार के अंतर्गत कुल 46000 प्रकरणों को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि पुन: देश में सर्वाधिक है। इसके अंतर्गत वनांचलों में निवासरत जन समुदाय को विभिन्न प्रकार के निस्तार संबंधी अधिकार, जैसे- गौण वन उत्पाद संबंधी अधिकार, मछली व अन्य जल उत्पाद तथा चारागाह अधिकार, विशेष पिछड़ी जाति एवं समुदायों, कृषकों को आवास अधिकार, सभी वन ग्रामों, पुराने रहवास क्षेत्रों, असर्वेक्षित ग्राम आदि को राजस्व ग्राम में बदलने के अधिकार आदि शामिल हैं।
- इसके अलावा वनांचल क्षेत्र में पाए जाने वाले लघु वनोपज संग्रहण के लिये 67 प्रजातियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है और इस वर्ष छ.ग. राज्य वन अधिकार मान्यता के प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा देश का 73 प्रतिशत लघु वनोपज का संग्रहण करने में सफलता प्राप्त की गई है।
- वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 4306 सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता-पत्र प्रदाय किये गए हैं। वन संसाधन अधिकार के प्रबंधन हेतु मान्यता प्रदान करने में छत्तीसगढ़ राज्य देश का प्रथम राज्य है, जहाँ व्यापक पैमाने पर वनवासियों के अधिकारों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए वन अधिकार-पत्र प्रदाय किये गए हैं।
- इस अधिकार के तहत ग्रामसभा को प्रदत्त मान्यता वाले वन क्षेत्रों के प्रबंधन का अधिकार दिया गया है। उक्त वनों के प्रबंधन हेतु प्रबंध योजना तैयार करने की कार्यवाही प्रगति पर है, जिसके लिये 19 ज़िलों के लगभग 2000 ग्रामों के हितधारकों को प्रबंध योजना तैयार कर कार्य आयोजना के साथ एकीकृत करते हुए प्रबंधन सुनिश्चित करना है।
- प्रबंध योजना में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता वाले वन के प्रबंधन हेतु समस्त प्रकार के सर्वेक्षण करते हुए प्रबंधन के सभी आयाम प्रस्तावित हैं। यहाँ यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रत्येक ईकाई वन भूमि पर अधिक-से-अधिक लाभ के लिये किस प्रकार का रोपण अथवा संरक्षण संबंधी कार्य प्रस्तावित किया जा सकता है।
- फाउंडेशन फॉर ईकोलॉजिकल सिक्युरिटी नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा राज्य के 19 ज़िलों के लगभग 700 ग्रामों में प्रसंस्करण एवं आय संसाधन में वृद्धि के लिये संभावनाओं की तलाश और उससे संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।
- इसी तरह प्रदान संस्था के द्वारा 05 ज़िलों के 36 गाँवों में कृषि के उन्नत तकनीक एवं प्रसंस्करण के विभिन्न आयामों का प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही रिक्त स्थानों पर कार्य आयोजना के प्रावधानों को प्रबंध योजना में एकीकृत करते हुए स्थानीय प्रजातियों के लिये बृहद रोपण हेतु योजना तैयार की जा रही है।
- राज्य में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत राज्य के 24 ज़िलों में लगभग 106 प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल 5492 हितग्राही लाभान्वित हुए हैं।

52 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान से होंगे सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

3 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षकों को प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य में 05 सितंबर, 2023 को राजभवन के दरबार हॉल में राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे।
- समारोह में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिये चयनित 48 शिक्षकों में से प्रत्येक को 21-21 हज़ार रुपए की राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश की महान विभूतियों की स्मृति में दिये जाने वाले पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रत्येक शिक्षक को 50-50 हज़ार रुपए और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- राज्य स्मृति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षक -
  - डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बक्शी स्मृति पुरस्कार: प्रधान पाठक ममता अहार (ज़िला रायपुर)
  - डॉ. मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार: प्रधान अध्यापक मधु तिवारी (ज़िला कोंडागाँव)

नोट :

- डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार: व्याख्याता रश्मि वर्मा (ज़िला रायगढ़)
- श्री गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार: शिक्षक एल.बी. इंदिरा चंद्रवंशी (ज़िला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई)

- राज्य शिक्षक पुरस्कार-2022 से सम्मानित होने वाले शिक्षक-
  - शिक्षक एल.बी. कृष्णपाल राणा और शिक्षक एल.बी. रूखमणी साहू (ज़िला कांकेर)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. देवेंद्र कुमार देवांगन और प्रधान पाठक ब्रजेश्वरी रावटे (ज़िला नारायणपुर)
  - शिक्षक महेश कुमार सेठिया और व्याख्याता रमेश कुमार उपाध्याय (ज़िला जगदलपुर)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. खेमलाल सिन्हा और उच्च श्रेणी शिक्षक ऊषा भूआर्य (ज़िला दंतेवाड़ा)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. श्रवण कुमार यादव और सहायक शिक्षक एल.बी. पुष्पलता साहू (ज़िला बालोद)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. तुलेश्वर कुमार सेन और शिक्षक एल.बी. पारूल चतुर्वेदी (ज़िला राजनांदगांव)
  - प्रधान पाठक यशवंत कुमार पटेल और शिक्षक एल.बी. सुश्री के. शारदा (ज़िला दुर्ग)
  - शिक्षक यक्ष चंद्राकर और प्रधान पाठक शिव कुमार बंजारे (ज़िला कबीरधाम)
  - शिक्षक एल.बी. ज्योति बनाफर और व्याख्याता एल.बी. सुषमा शुक्ला शर्मा (ज़िला बेमेतरा)
  - व्याख्याता एल.बी. अनिल कुमार प्रधान और सहायक शिक्षक एल.बी. डोलामणी साहू (ज़िला महासमुंद)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. संतोष कुमार तारक और सहायक शिक्षक एल.बी. लताबेला मोंगेरे (ज़िला गरियाबंद)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. उत्तम कुमार देवांगन और सहायक शिक्षक एल.बी. डॉ. गोपा शर्मा (ज़िला रायपुर)
  - व्याख्याता एल.बी. राजूराम साहू और सहायक शिक्षक एल.बी. दीनबंधु सिन्हा (ज़िला धमतरी)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. विनोद कुमार डड़सेना और प्रधान पाठक आशा साहू (ज़िला बलौदाबाज़ार-भाटापारा)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. राजेश कुमार सूर्यवंशी और व्याख्याता एल.बी. अनुराग तिवारी (ज़िला जांजगीर-चांपा)
  - व्याख्याता एल.बी. भोजराम पटेल और सहायक शिक्षक एल.बी. संतोष कुमार पटेल (ज़िला रायगढ़)
  - व्याख्याता एल.बी. सुशील कुमार पटेल और सहायक शिक्षक एल.बी. रामधन पटेल (ज़िला बिलासपुर)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. अदिति शर्मा और सहायक शिक्षक एल.बी. भीष्म प्रसाद त्रिपाठी (ज़िला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. गोकुल प्रसाद मार्बल और शिक्षक मुकुंद केशव उपाध्याय (ज़िला कोरबा)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. पुष्पेंद्र कुमार कौशिक और सहायक शिक्षक एल.बी. मीरा देवांगन (ज़िला सक्ती)
  - सहायक शिक्षक एल.बी. रूद्र प्रताप सिंह राणा और व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य डॉ. विनोद पांडेय (ज़िला कोरिया)
  - व्याख्याता निशा सिंह और सहायक शिक्षक एल.बी. दिनेश कुमार साहू (ज़िला सूरजपुर)
  - व्याख्याता अनामिका चक्रवर्ती और व्याख्याता एल.बी. अंचल कुमार सिन्हा (ज़िला सरगुजा)
  - व्याख्याता प्रभारी प्राचार्य बाबूलाल लहरे और सहायक शिक्षक एल.बी. रमेश कुमार साकेत (ज़िला बलरामपुर)

राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार-2023 की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार 2023 के लिये 52 शिक्षकों के नाम की घोषणा की। चयनित शिक्षकों को आगामी वर्ष शिक्षक दिवस के मौके पर सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राजभवन के दरबार हॉल में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित गरिमामय समारोह में 52 शिक्षकों को राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2022 से सम्मानित किया गया तथा आगामी वर्ष सम्मानित होने वाले शिक्षकों के नामों की घोषणा की गई।

नोट :

- शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में चार उत्कृष्ट शिक्षकों- रायपुर ज़िले की ममता अहार (प्रधानपाठिका) को डॉ. पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार, कोंडागाँव ज़िले की मधु तिवारी (प्रधान अध्यापिका) को डॉ. मुकुटधर पांडेय स्मृति पुरस्कार, रायगढ़ ज़िले की रश्मि वर्मा (व्याख्याता) को डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई ज़िले की इंदिरा चंद्रवंशी (शिक्षक एल.बी.) को गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- इसी तरह प्रधान पाठक व्याख्याता, उच्च क्षेणी शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक एल. बी. तथा सहायक शिक्षक एल. बी., वर्ग के 48 उत्कृष्ट शिक्षकों को वर्ष 2022 के लिये राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- राज्य शिक्षक सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023 के लिये चयनित शिक्षक-
  - व्याख्याता नेहा नाथ और शिक्षक एलबी कुमारी माधुरी उके (ज़िला दंतेवाड़ा)
  - प्रधान पाठक मधु सोनवानी और व्याख्याता नीतु सिंह यादव (ज़िला सरगुजा)
  - व्याख्याता एलबी रीता गिरि और प्रधान पाठक विनिता सिंह (ज़िला सूरजपुर)
  - व्याख्याता एलबी धमेंद्र कुमार साहू और व्याख्याता डॉ. भरतलाल साहसी (ज़िला बालोद)
  - व्याख्याता एलबी टुमनु गोसाईं और अयोध किशोर गुप्ता (ज़िला जशपुर)
  - प्रधान पाठक जयमाला और हपका मुत्ता (ज़िला सुकमा)
  - सहायक शिक्षक नीलकंठ कोमरे और अंगद सलामें (ज़िला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी)
  - सहायक शिक्षक स्वप्निल सिंह पवार और शिक्षक एलबी अर्चना सामुएल मसीह (ज़िला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)
  - व्याख्याता एलबी मानस साहू और सहायक शिक्षक एलबी महादीप जंघेल (ज़िला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई)
  - व्याख्याता सेवक राम निषाद और व्याख्याता एलबी पवन कुमार सेन (ज़िला उत्तर बस्तर कांकेर)
  - व्याख्याता तनुजा देवांगन और उच्च श्रेणी शिक्षक सरस्वती नाग (ज़िला कोंडागाँव)
  - सहायक शिक्षक एलबी श्वेता सोनी और अर्पणा मिश्रा (ज़िला कोरिया)
  - व्याख्याता एलबी गोकुल दास जंघेल और जयप्रकाश साहू (ज़िला राजनांदगाँव)
  - शिक्षक एलबी कविता हिरवानी और व्याख्याता एलबी लता मानिकपुरी (ज़िला नारायणपुर)
  - व्याख्याता एलबी दिनेश कुमार चतुर्वेदी और सहायक शिक्षक एलबी कामता प्रसाद सिंह (ज़िला जांजगीर-चांपा)
  - सहायक शिक्षक एलबी सुनिता यादव और व्याख्याता पूनम सिंह साहू (ज़िला सारंगढ़-बिलाईगढ़)
  - सहायक शिक्षक एलबी हिमकल्याणी और व्याख्याता एलबी भुवनलाल साहू (ज़िला बेमेतरा)
  - व्याख्याता प्रमोद कुमार कन्नौजे और व्याख्याता एलबी शैलेंद्र कुमार नायक (ज़िला महासमुंद)
  - शिक्षक श्याम कुमार गुप्ता और प्रधान पाठक विनोद कुमार पंथ (ज़िला बलरामपुर)
  - शिक्षक एलबी डॉ. सत्यनारायण तिवारी और प्रधान पाठक जितेंद्र गेंदले (ज़िला मुंगेली)
  - सहायक शिक्षक एलबी डिगेश्वर कुमार साहू और उच्च श्रेणी शिक्षक किशोर कुमार निर्मलकर (ज़िला गरियाबंद)
  - व्याख्याता एलबी ज्योति मगर और डॉ. आशीष नायक (ज़िला धमतरी)
  - प्रधान पाठक डॉ. मनीषा त्रिपाठी और सुशील कुमार गुप्ता (ज़िला रायगढ़)
  - व्याख्याता भुपेंद्र कुमार राठौर और सहायक शिक्षक वसुंधरा कुर्रे (ज़िला कोरबा)
  - व्याख्याता मीरा हिरवानी और मोहम्मद अकबर खान (ज़िला जगदलपुर)
  - प्रधान पाठक पवन कुमार सिन्हा और शिक्षक एलबी ककेम नारायण (ज़िला बीजापुर)

नोट :

राज्य स्तरीय
शिक्षक सम्मान समारोह

राज्य स्तरीय
शिक्षक सम्मान समारोह
05 सितम्बर - 2023
समस्त शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन

नोट :

स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ के सरगुजा ज़िले के स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल ब्रह्मपारा, अंबिकापुर के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देशभर के 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किये।
- इस शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कारस्वरूप 50 हज़ार रुपए नकद, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया।
- सरगुजा ज़िले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम विद्यालय के प्राचार्य डॉ. बृजेश पांडेय को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित डॉ. बृजेश पांडेय ने विज्ञान के प्रति अभिरुचि जगाने के साथ बाल वैज्ञानिकों को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। उनके दिशा-निर्देशन में कई बाल वैज्ञानिकों का मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित हो चुका है।
- विदित है कि डॉ. पांडेय वर्ष 2018 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्राथमिक शिक्षा के बच्चों के लिये एक्टिविटी बुक के निर्धारण में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
- गौरतलब है कि प्रदेश में बच्चों को अंग्रेज़ी माध्यम की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिये स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेज़ी माध्यम स्कूलों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों के बच्चे भी अंग्रेज़ी माध्यम में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्वामी आत्मानंद स्कूलों की संख्या भी दिनों-दिन बढ़ रही है और अभिभावकों में इन स्कूलों के प्रति विश्वास बढ़ा है।

जी-20 में आईं फर्स्ट लेडी को बस्तर की महिलाओं की ओर से मिलेट का उपहार

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेशभर से आए 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिये सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों को योग के महत्त्व के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन-शैली के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को महती ज़िम्मेदारी सौंपी। इसे पूरा करते हुए आयोग द्वारा प्रदेश में लगभग 50 नियमित नि:शुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किये गए हैं। सभी संभागों के योगसाधकों में प्रशिक्षण देकर गाँव-गाँव तक योग का प्रचार किया जा रहा है।
- आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक वार्डों में नि:शुल्क योग केंद्र खोले गए हैं।
- सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सेतुबंध आसन के साथ-साथ अन्य आसनों, प्राणायामों तथा ध्यान का अभ्यास भी किया गया।

मुख्यमंत्री ने 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों को 23.93 करोड़ रुपए का किया भुगतान

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से 'गोधन न्याय योजना' के अंतर्गत ऑनलाईन राशि वितरण कार्यक्रम में हितग्राहियों के बैंक खातों में 23 करोड़ 93 लाख रुपए अंतरित किये।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 'गोधन न्याय योजना' के हितग्राहियों के खाते में ऑनलाईन अंतरित की गई राशि में गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रुपए, गोठान समितियों को 1.63 करोड़ रुपए एवं स्व-सहायता समूहों की 1.14 करोड़ रुपए की लाभांश राशि के साथ ही स्व-सहायता समूहों को 12.32 करोड़ रुपए तथा सहकारी समितियों को 1.23 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि और स्वावलंबी गोठान समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों को 2.25 करोड़ रुपए की मानदेय राशि शामिल है।
- गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को 29 करोड़ 93 लाख रुपए के भुगतान के बाद अब तक कुल 581.24 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोठानों में 15 अगस्त से 31 अगस्त तक क्रय किये गए 2.68 लाख क्विंटल गोबर के एवज में गोबर विक्रेताओं को 5.36 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान किया। गोठानों में अब तक 133.22 क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसकी एवज में पशुपालन किसानों को 261.08 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। 5.36 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद गोबर क्रय की कुल राशि 266.44 करोड़ रुपए हो गई है।
- गोठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को भुगतान की जाने वाली 2.77 करोड़ रुपए की राशि के बाद इनको होने वाले भुगतान की राशि 275.01 करोड़ रुपए हो गई है।
- मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गोबर से कम्पोस्ट खाद के उत्पादन से जुड़े स्व-सहायता समूहों को कम्पोस्ट खाद के विक्रय पर प्रति किलोग्राम एक रुपए के मान से कुल 12 करोड़ 32 लाख रुपए तथा सहकारी समितियों को प्रति किलो 10 पैसे मान से कुल 1 करोड़ 23 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में ऑनलाईन जारी किये। मुख्यमंत्री स्वावलंबी गोठानों के 42 हज़ार 644 सदस्यों को मानदेय के रूप में 2 करोड़ 25 लाख रुपए उनके बैंक खातों में अंतरित किये।
- गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में स्वावलंबी गोठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में निर्मित एवं संचालित 10288 गोठानों में से 6252 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं से गोबर क्रय कर रहे हैं। स्वावलंबी गोठानों ने अब तक 76 करोड़ 42 लाख रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठानों में चार रुपए लीटर की दर से गोमूत्र खरीदकर महिला स्व-सहायता समूह की महिलाएँ इससे ब्रह्मास्त्र और जीवामृत तैयार कर रही हैं, जिसे किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान अब महँगे पेस्टीसाइट के बदले जैविक कीटनाशक ब्रह्मास्त्र और जीवामृत का उपयोग करने लगे हैं।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हर साल धान खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। इस साल आशा है कि 125 लाख मीट्रिक धान खरीदी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ ने सेतुबंध आसन के प्रदर्शन के लिये गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित स्वर्गीय बलबीर जुनेजा इंडोर स्टेडियम में प्रदेशभर से आए 2000 से अधिक योगाभ्यासियों ने तिरंगे रंग का प्रतिरूप बनाते हुए एक साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिये सेतुबंध आसन का सामूहिक प्रदर्शन किया।
- विदित है कि छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा लोगों को योग के महत्त्व के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवन-शैली के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता में रखते हुए छत्तीसगढ़ योग आयोग को महती ज़िम्मेदारी सौंपी। इसे पूरा करते हुए आयोग द्वारा प्रदेश में लगभग 50 नियमित नि:शुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू किये गए हैं। सभी संभागों के योगसाधकों में प्रशिक्षण देकर गाँव-गाँव तक योग का प्रचार किया जा रहा है।

नोट :

- आम नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र के 90 प्रतिशत से अधिक वार्डों में नि:शुल्क योग केंद्र खोले गए हैं।
- सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में सेतुबंध आसन के साथ-साथ अन्य आसनों, प्राणायामों तथा ध्यान का अभ्यास भी किया गया।

हीरक जयंती पर मुख्यमंत्री ने रायपुर मेडिकल कॉलेज के 700 बिस्तर क्षमता वाले नए चिकित्सालय भवन का किया भूमिपूजन

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में 700 बिस्तर क्षमता वाले नए एकीकृत चिकित्सालय भवन का भूमिपूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल के लिये 322 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सर्वसुविधायुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा।
- मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज ऑडिटोरियम में महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ भी किया। आज से ठीक 60 साल पहले 9 सितंबर, 1963 को रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी।

नोट :

- उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज का 60 साल का सफर शानदार रहा है। इससे संबद्ध अस्पताल प्रदेशवासियों के लिये बड़ी उम्मीद है। एशिया की सबसे एडवांस्ड मशीनरी भी यहाँ उपलब्ध है। सिंहदेव ने बताया कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सिक्वेंसिंग लैब के लिये मंज़ूरी मिल गई है।
- चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै ने कार्यक्रम में कहा कि रायपुर मेडिकल कॉलेज प्रदेश का सबसे बड़ा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है। यहाँ लगातार बढ़ रही मरीज़ों की संख्या को देखते हुए सर्वसुविधायुक्त एकीकृत चिकित्सालय भवन की ज़रूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। आज भूमिपूजन होने के बाद जल्दी ही इसका निर्माण भी शुरू हो जाएगा।
- डीन डॉ. तृप्ति नागरिया ने बताया कि 1963 में आज ही के दिन 60 विद्यार्थियों के साथ इसकी यात्रा शुरू हुई थी। अब यहाँ एमबीबीएस की 230 और पीजी की 150 सीटें हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल की क्षमता 700 बिस्तरों से बढ़कर 1248 हो गई है।
- नए एकीकृत चिकित्सालय भवन में 700 बिस्तर बढ़ने से यहाँ बिस्तरों की संख्या करीब दो हज़ार हो जाएगी। दो हज़ार बिस्तर क्षमता वाला यह मध्य भारत का एकमात्र अस्पताल होगा। चिकित्सालय में सुविधा बढ़ने से लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा।
- प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने की दिशा में राज्य सरकार का यह एक बड़ा कदम है। इसके बनने से राजधानी के नागरिकों को अत्याधुनिक सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी।
- डॉ. भीमराव स्मृति चिकित्सालय रायपुर में बनने वाले 700 बिस्तर के इस अस्पताल में बेसमेंट फ्लोर, लोवर ग्राउंड फ्लोर तथा भूतल के अलावा सात तल होंगे। इस अस्पताल में सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल की सभी सुविधाएँ मरीज़ों को मिलेंगी।
- इस एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन का निर्माण 70 हज़ार 896 वर्ग मीटर में होगा। भवन में फायर फाइटिंग सिस्टम, एचवीएसी सिस्टम, आईबीएमएस सिस्टम आदि का प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार का महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला

चर्चा में क्यों ?

11 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को सरकारी नौकरी से प्रतिबंधित कर दिया है। इस संबंध में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि बीते 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालिकाओं और महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरी से प्रतिबंधित करने की घोषणा की थी।
- सामान्य प्रशासन द्वारा सभी विभागों, राजस्व मंडल के अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों को जारी निर्देश में कहा गया है कि शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी, जिनके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध जो कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हों, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाए।
- राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान है कि कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। परंतु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिये प्रशासनिक, व्यावहारिक और विधिक कई स्तरों पर तत्परता से काम किया है। प्रदेश के 547 थानों, चौकियों में महिला सेल की स्थापना की गई है, ताकि पीड़ित महिलाएँ नि:संकोच अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकें।

नोट :

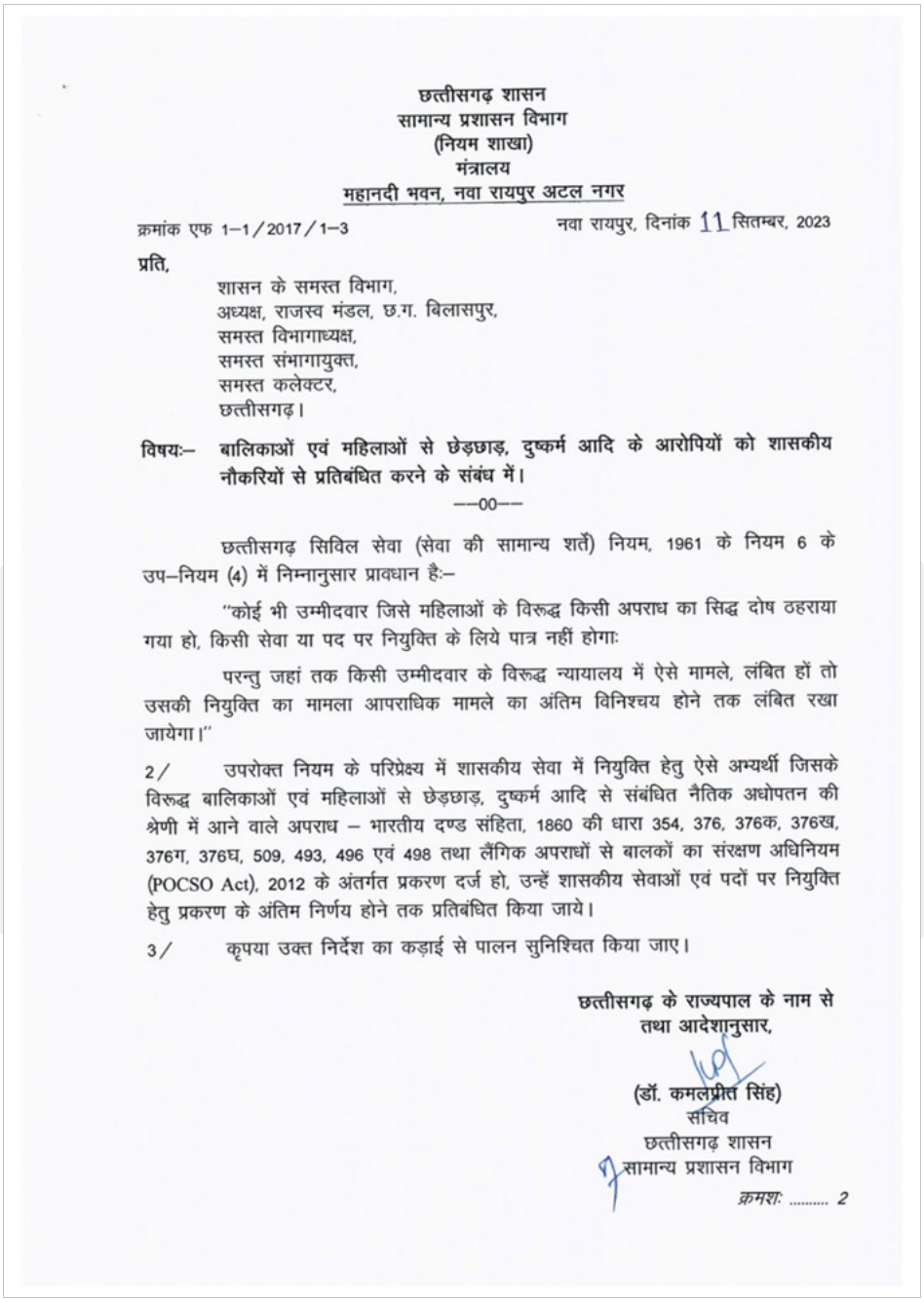

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(नियम शाखा)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

क्रमांक एफ 1–1/2017/1–3 नवा रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर, 2023

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, छ.ग. बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः– बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित करने के संबंध में।

––00––

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप–नियम (4) में निम्नानुसार प्रावधान हैः–

"कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः

परन्तु जहां तक किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।"

2/ उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अधोपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध – भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 354, 376, 376क, 376ख, 376ग, 376घ, 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज हो, उन्हें शासकीय सेवाओं एवं पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जाये।

3/ कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमशः 2

- ज़िला स्तर पर प्रत्येक ज़िले में महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। प्रत्येक ज़िला मुख्यालय में घरेलू हिंसा एवं महिला उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम हेतु महिला परामर्श केंद्र की स्थापना की गई है।
- राज्य के 04 बड़े ज़िले बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग तथा सरगुजा में महिला थाना स्थापित किया गया है। राज्य के 6 ज़िले रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, बिलासपुर, रायगढ़ तथा जांजगीर-चांपा में महिला विरुद्ध अपराध अनुसंधान ईकाई की स्थापना की गई है।
- राज्य पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु अभिव्यक्ति ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिसके एक लाख 85 हज़ार से अधिक पंजीकृत यूजर्स हैं।

नोट :

- महिला सुरक्षा और अपराधों को नियंत्रण करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों को चिन्हाकिंत कर संवेदनशील स्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन शोषण को रोके जाने के संबंध में प्रत्येक ईकाई में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है।
- बालिकाओं और युवतियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये स्कूल-कॉलेज एवं संवेदनशील स्थानों पर महिला पुलिस पेट्रोलिंग टीम द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। इसके साथ ही विशेषज्ञ अथवा प्रशिक्षित महिला पुलिस अधिकारियों के माध्यम से महिलाओं के विरूद्ध अपराधों की रोकथाम के लिये जागरूकता अभियान भी संचालित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में 'कमर्शियल हब', 'एरोसिटी' और 'शहीद स्मारक'की रखी आधारशिला

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर अटलनगर के सेक्टर-35 में आयोजित समारोह में तीन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं 'कमर्शियल हब', 'एरोसिटी' और 'शहीद स्मारक'का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- नवा रायपुर में निवेश, बसाहट और वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेक्टर-23, 24, 34, 35 और 40 में 1083 एकड़ में 'कमर्शियल हब'विकसित किया जा रहा है।
- इसी तरह नवा रायपुर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोज़गार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट ग्राम बरोदा एवं रमचंडी के चिन्हांकित 216.63 एकड़ में 'एरोसिटी'विकसित की जा रही है।
- 'शहीद स्मारक'की स्थापना नवा रायपुर के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्हीआईपी बटालियन में 13 एकड़ में की जा रही है।
- कमर्शियल हब:
  - कमर्शियल हब के प्रथम चरण में 20 व्यवसायों के लगभग 1,000 थोक व्यावसायिक दुकानों के विकास हेतु भू-खंडों का प्रावधान किया गया है जिसमें थोक किराना, अगरबत्ती, होलसेल बारदाना, दाल मिल, पेपर ट्रेड आदि हेतु पृथक्-पृथक् प्रावधान किया गया है।
  - कमर्शियल हब के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 'कमर्शियल हब'के सिटी लेवल अधोसंरचना तथा प्रथम चरण के 125 एकड़ में अधोसंरचना का विकास 195.51 करोड़ रुपए की राशि से किया जाएगा।
  - इस परियोजना के लिये चिन्हांकित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 30 एवं भारत माला परियोजना के अलॉइमेंट के निकट स्थित है तथा उक्त भूमि को रेलवे कनेक्टिविटी भी प्राप्त है। चिन्हांकित भू-खंड स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से लगभग 12 किमी. पर स्थित है।
  - चिन्हांकित भूमि ग्राम निमोरा, उपरवारा, परसट्टी, बेंद्री, केंद्री, झाँकी एवं मुड़पार में स्थित है। उक्त भू-खंड का भू-उपयोग सार्वजनिक तथा अर्ध- सार्वजनिक से मिश्रित भू-उपयोग में किया गया है।

नोट :

- यह थोक व्यावसायिक बाज़ार न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आस-पास के अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये भी लाभदायक होगा। इस परियोजना में थोक व्यवसाय से जुड़ी सभी सुविधाएँ एवं भौतिक अधोसंरचना उच्च मानकों के अनुसार प्रदान की जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन से आस-पास के क्षेत्र में रोज़गार के सृजन होने की संभावनाएँ हैं।

- एरोसिटी : वाणिज्यिक संस्थान, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल का प्रावधान
  - नया रायपुर अटल नगर के लेयर-3 में यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने, एयरपोर्ट क्षेत्र के वाणिज्यिक विकास तथा रोज़गार सृजन हेतु स्वामी विवेकानंद विमानतल के निकट एरोसिटी विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी, 2023 को एरोसिटी की स्थापना की घोषणा की थी।
  - एरोसिटी के लिये नवा रायपुर के ग्राम बरोदा और रमचंडी में लगभग 216.63 एकड़ भूमि चिन्हांकन की गई है। चिन्हांकित भू-खंड में निजी स्वामित्व की भूमि शामिल होने के कारण एरोसिटी परियोजना का विकास नगर विकास योजना की तर्ज पर किये जाने का निर्णय लिया गया है।
  - बाजार मूल्यांकन एवं प्राधिकरण का वित्तीय हित देखते हुए प्रथम चरण में लगभग 24.85 एकड़, क्षेत्रफल की भूमि को विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया।
  - शासकीय स्वामित्व की 15.45 एकड़ भूमि पर तैयार किये गए अभिन्यास में 0.62 एकड़ से 3.01 एकड़ तक के 04 वाणिज्यिक भू-खंड, 0.82 एकड़ के 01 शॉपिंग कॉम्पलेक्स एवं 1.44 एकड़ भूमि 01 होटल हेतु प्रस्तावित है।
  - एरोसिटी के विकास हेतु राज्य शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- शहीद स्मारक:
  - नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र के ग्राम परसदा (सेक्टर-3) में व्ही.आई.पी. बटालियन के लिये 42.931 एकड़ भूमि चिन्हांकित की गई है। इसमें से 13 एकड़ में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी।
  - इस प्रस्तावित परियोजना में शहीद स्मारक लगभग 07 एकड़ भूमि पर 2700 शहीदों के नाम उत्कीर्ण किये जाने हेतु दीवारों का निर्माण, छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक का निर्माण, स्मारक म्यूजियम, 21 प्लाटून हेतु परेड ग्राउंड, बगलर प्लेटफार्म, लगभग 400 दर्शकों हेतु दीर्घा, विशिष्ट अतिथि दीर्घा, 60 जवानों के लिये बैरक तथा पार्किंग, फाउंटेन, सिचाई इत्यादि की व्यवस्था की जाएगी। राज्य शासन द्वारा इसके लिये 47.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।

मुख्यमंत्री ने राज्य कृषि विपणन बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया तथा छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड के नवीन कार्यालय भवन का लोकार्पण किया तथा नए बनने वाले छत्तीसगढ़ कृषि भवन की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड के नवीन भवन का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर करने की घोषणा की। नवा रायपुर के सेक्टर-24 में 40 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किये गए इस भवन में बीज निगम का कार्यालय भी संचालित होगा।
- लगभग 1 लाख 58 हज़ार वर्गफीट में बनाए गए इस भवन से कृषि संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ संचालित होंगी जिसका लाभ किसानों को मिलेगा।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की सुविधा के लिये राज्य में मंडी का विस्तार किया जा रहा है। राज्य में लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जानी है। इसको देखते हुए धान संग्रहण केंद्रों को भी मंडी के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इसके अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवा रायपुर के सेक्टर-19 में 49 करोड़ 50 लाख की लागत से 3.14 एकड़ में बनने वाले नए पाँच मंज़िला छत्तीसगढ़ कृषि भवन का भूमिपूजन किया एवं आधारशिला रखी।

नोट :

- कृषि भवन में कृषि से संबंधित समस्त विभाग-कृषि संचालनालय, कृषि अभियांत्रिकी, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, जल ग्रहण प्रबंधन, पशुधन विकास, मछली पालन के संचालनालय होंगे। भवन में कृषि मंत्री एवं कृषि उत्पादन आयुक्त का कार्यालय भी स्थापित होगा।
- एकीकृत कृषि भवन के निर्माण से विभाग की सहयोगी संस्थाओं के बीच आपसी सामंजस्य में वृद्धि होगी, जिससे कृषि विकास के कार्यों में गति आएगी तथा राज्य भर से आने वाले कृषकों की समस्याओं का निपटारा एक ही छत के नीचे संभव हो सकेगा। भविष्य में कृषि भवन को कृषि क्षेत्र के विकास हेतु एक 'समन्वित संसाधन केंद्र' के रूप में विकसित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मिली मान्यता

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान से मान्यता मिल गई है।

प्रमुख बिंदु

- छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् के अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् को सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड की अधिकृत सूची में शामिल कर लिया है। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे मंज़ूरी दे दी गई है।
- राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने से छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी नौकरियों में भर्ती और संस्कृत के क्षेत्र में आगे पढ़ाई करने का अवसर मिल सकेगा।

छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामण्डलम
रायपुर, (छ.ग.)

नोट :

- विदित है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा और भाषा की प्रतिष्ठा के लिये छत्तीसगढ़ संस्कृत बोर्ड, सम्प्रति छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्यामंडलम् का गठन 2003 में किया था।

जलजीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले को केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय की ओर से मिला प्रशस्ति-पत्र

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2023 को केंद्रीय जलशक्ति, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने छत्तीसगढ़ के नारायणपुर ज़िले को आकांक्षी ज़िले के अंतर्गत जलजीवन सर्वेक्षण 2023 में उत्कृष्ट कार्य के लिये प्रशस्ति-पत्र से सम्मानित किया।

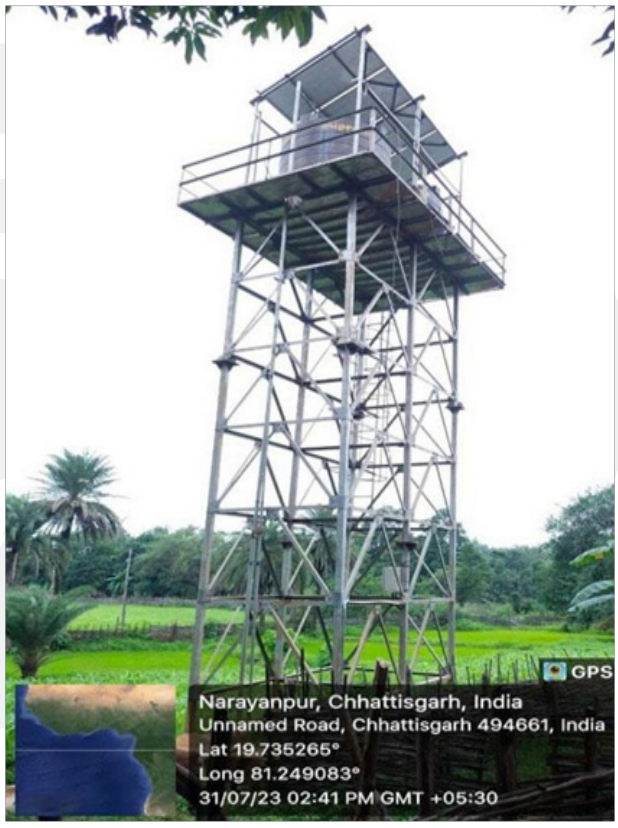

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि बेहद कठिन बसाहटों वाले नारायणपुर ज़िले के गाँव-गाँव में हर ग्रामीण को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य था। इसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिये केंद्र सरकार ने आकांक्षी ज़िले के अंतर्गत नारायणपुर ज़िले को सम्मानित किया।
- केंद्र सरकार द्वारा जलजीवन सर्वेक्षण 1 अक्तूबर 2022 से 30 जून, 2023 तक कराया गया। इसमें आकांक्षी ज़िलों के अंतर्गत नारायणपुर ज़िले का कार्य उत्कृष्ट पाया गया।
- इस ज़िले के लिये जलजीवन मिशन ने 30 हज़ार 322 परिवारों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने का लक्ष्य रखा था। इसमें 18 हज़ार 72 घरों तक नल कनेक्शन पहुँचाया जा चुका है। 14 गाँव ऐसे हैं, जहाँ शत-प्रतिशत परिवारों को कनेक्शन दिया जा चुका है।
- वर्तमान स्थिति में राज्य द्वारा औसतन प्रतिदिन 7000 घरेलू कनेक्शन की उपलब्धि अर्जित की जा रही है तथा 60 प्रतिशत परिवारों को घरेलू कनेक्शन दिया जा चुका है। अब तक राज्य के कुल 422 ग्रामों को हर घर जल प्रमाणीकरण किया जा चुका है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि नारायणपुर ज़िले में दो विकासखंड ओरछा और नारायणपुर हैं। विकासखंड ओरछा का अधिकांश क्षेत्र अबूझमाड़ के अंतर्गत आता है जो लगभग 4 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ पहाड़ एवं घने जंगलों से घिरा हुआ है। अभी तक इन क्षेत्रों का सर्वे भी नहीं हो पाया है।
- ज्ञातव्य है कि राज्य में जलजीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के कुल 43 हज़ार 974 शाला (86.78 प्रतिशत), 41 हज़ार 719 आंगनबाड़ी केंद्र (83.39 प्रतिशत) एवं 5246 स्वास्थ्य केंद्र (97.86 प्रतिशत) में रनिंग वाटर उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य के शत-प्रतिशत अर्थात् 2470 आश्रमशालाओं में रनिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- राज्य के 7 ज़िलों-धमतरी, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, मुंगेली, जांजगीर-चांपा एवं सक्ती ज़िले में 70 प्रतिशत से अधिक घरेलू कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।
- नारायणपुर ज़िले में 6 ग्रामों में हर घर जल उत्सव मनाकर प्रमाणीकरण कराया गया है। नारायणपुर ज़िले में हर घर जल पूर्ण करने के प्रयासों के अंतर्गत विकासखंड ओरछा के अंदरूनी ग्राम उदिदगाँव, गुलुमकोड़ो, कोकोड़ी, कुंडला, खडकागाँव, गुरिया एवं पल्ली आदि गाँवों में कार्य पूर्णता पर है।

डेटा-एआई क्लब के गठन के लिये रायपुर ज़िला प्रशासन और आईजेब्रा-एआई के मध्य हुआ एमओयू

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2023 को रायपुर ज़िले के कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे की उपस्थिति में ज़िला प्रशासन और आईजेब्रा-एआई (ige-bra-AI) के मध्य एमओयू हुआ, जिसके तहत ज़िले के तीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल (SEGES) में डेटा-एआई क्लब का गठन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर अगले शिक्षा सत्र से स्कूली बच्चों के पाठ्यक्रम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी अत्याधुनिक तकनीकी की जानकारी शामिल करने की घोषणा की है। ज़िला प्रशासन ने इसी दिशा में त्वरित क्रियान्वयन करते हुए यह कदम उठाया हैं। यह महत्त्वपूर्ण कदम उठाने वाला रायपुर पहला ज़िला है।

नोट :

- इस एमओयू में ज़िला प्रशासन की तरफ से ज़िला पंचायत के सीईओ अबिनाश मिश्रा और कंपनी के निर्देशक चिरंजीवी मडाला ने हस्ताक्षर किया।
- इस एमओयू के तहत स्वामी आत्मानंद आर.डी तिवारी आमापारा, स्वामी आत्मानंद बी.पी पुजारी राजातालाब और स्वामी आत्मानंद शहीद स्मारक फाफाडीह में एआई क्लब का गठन होगा।
- इससे इन स्कूलों के विद्यार्थियों में एआई के प्रति समझ विकसित होगी। विद्यार्थी विज्ञान की इस नवीनतम तकनीक से परिचित होंगे और उसका उपयोग प्रोजेक्ट तथा अन्य कार्यों में कर सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ के बच्चों में विज्ञान के प्रति अधिक रुचि पैदा होगी, साथ ही वे देश ही नहीं, बल्कि विश्व में अन्य युवाओं के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर कार्य करेंगे।
- इस क्लब में विद्यार्थियों को संबंधित संस्था के प्रशिक्षकों के द्वारा एआई क्लब में पढ़ाया जाएगा और वर्कशॉप होगी। साथ ही प्रोजेक्ट-मॉडल प्रदर्शित किये जाएंगे।
- गौरतलब है कि यह आईजेब्रा-एआई अमेरिका की कंपनी है, जो एआई के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसका उद्देश्ययुवाओं को एआई के प्रति शिक्षित करना है।

प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाएँ राष्ट्र को समर्पित कीं।

प्रमुख बिंदु

- इन रेल परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण-1, चंपा से जमगा के बीच तीसरी रेल लाइन, पेंद्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन और तलाईपल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली एमजीआर (मेरी-गो-राउंड) प्रणाली शामिल हैं।
- ये रेल परियोजनाएँ इस क्षेत्र में यात्रियों की आवाजाही के साथ-साथ माल ढुलाई को सुगम बनाकर सामाजिक-आर्थिक विकास को गति प्रदान करेंगी।
- छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना के चरण-1 को महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ति-मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है और इसमें खरसिया से धरमजयगढ़ तक 124.8 किलोमीटर की रेल लाइन शामिल है। इसमें गेर-पेलमा के लिये एक स्पर लाइन और छल, बरौद, दुर्गापुर अन्य कोयला खदानों को जोड़ने वाली तीन फीडर लाइनें शामिल हैं।
- लगभग 3,055 करोड़ रुपए की लागत से बनी यह रेल लाइन विद्युतीकृत ब्रॉड गेज लेवल क्रॉसिंग और यात्री सुविधाओं के साथ फ्री पार्ट डबल लाइन से सुसज्जित है। यह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित मांड-रायगढ़ कोयला क्षेत्रों से कोयला परिवहन के लिये रेल कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।

नोट :

- पेंद्रा रोड से अनूपपुर के बीच तीसरी रेल लाइन 50 किमी लंबी है और लगभग 516 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है। चांपा और जामगा रेल खंड के बीच 98 किलोमीटर लंबी तीसरी लाइन लगभग 796 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। नई रेल लाइनों से इस इलाके में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन तथा रोज़गार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी।
- 65 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत एमजीआर (मैरी-गो-राउंड) प्रणाली एनटीपीसी की तलाईपल्ली कोयला खदान से छत्तीसगढ़ में 1600 मेगावाट के एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन तक कम लागत में उच्च श्रेणी का कोयला लाने का काम करेगी। इससे एनटीपीसी लारा से कम लागत के और विश्वसनीय बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मज़बूत होगी।
- इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के 9 ज़िलों में 50 बिस्तरों वाले 'क्रिटिकल केयर ब्लॉक'का शिलान्यास भी किया।
- प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत दुर्ग, कोंडागाँव, राजनांदगाँव, गरियाबंद, जशपुर, सूरजपुर, सरगुजा, बस्तर और रायगढ़ ज़िलों में नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जाएंगे, जिनकी कुल लागत 210 करोड़ रुपए होगी।
- जनजातीय आबादी के बीच विशेषरूप से होने वाले सिकल सेल रोग से उपजी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने जाँची गई आबादी को एक लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड वितरित किये।
- उल्लेखनीय है कि सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन (एनएसएईएम) के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के शहडोल में किया गया था।

शालेय राज्य स्तरीय ताईक्वांडो में जशपुर को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 काँस्य पदक मिले

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कोरबा में 10 से 14 सितंबर तक आयोजित 23 वीं शालेय राज्य स्तरीय ताईक्वांडो प्रतियोगिता में जशपुर ज़िले को 2 स्वर्ण, 2 रजत और 5 काँस्य पदक प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- जशपुर कलेक्टर डॉ. रवि मित्तल ने बताया कि ज़िले के आयुष यादव पिता अखिलेश यादव, प्रतीक बड़ा पिता निर्मल बड़ा का चयन राष्ट्रीय स्तर में ताईक्वांडो प्रतियोगिता के लिये हुआ है।
- वहीं ज़िले के युवराज कुमार, बिनेशन लकड़ा को रजत पदक मिला है। इसी प्रकार करण राम, मनीष भगत, रुद्र प्रताप सिंह, ईशप्रिया लकड़ा, नेहा नागवंशी ने काँस्य पदक प्राप्त किया।

नोट :

- ताईक्वांडो कोच ने बताया कि नेशनल के लिये चयनित खिलाड़ी दिसंबर में मध्य प्रदेश के बैतुल में आयोजित नेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, जिसके लिये बच्चों को खेल में पारंगत किया जा रहा है।

संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक: बालोद बना ओवरऑल चैंपियन

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बालोद ज़िला ओवरऑल चैंपियन बना है।

प्रमुख बिंदु

- दुर्ग संभाग के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरई में आयोजित संभाग स्तरीय ओलंपिक के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में बालोद ज़िले के खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन से ओवर आल चैंपियन का खिताब अर्जित किया।

नोट :

- बालोद के अलग-अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में सर्वाधिक 38 गोल्ड मैडल प्राप्त किये।
- प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के अंतर्गत 0-18 वर्ष तक के आयु वर्ग के विभिन्न खेलों में पिठ्ठूल, संखली, गेडी दौड़, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद तथा कुश्ती 50 किग्रा. वर्ग के अंतर्गत खेले गए मैच में बालोद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
- इसी तरह खो-खो और रस्साकशी में द्वितीय स्थान तथा गिल्ली डंडा के अलावा कुश्ती प्रतियोगिता के अंतर्गत 51-60 किग्रा. वर्ग, 61-70 किग्रा. वर्ग, 71-80 किग्रा. वर्ग एवं 80 किग्रा. वर्ग के मैच में बालोद जिले को तृतीय स्थान मिला है।
- महिला वर्ग के अंतर्गत 0- से 18 वर्ष के आयु वर्ग के पिठ्ठूल, फुगड़ी, लंबी कूद, रस्सी कूद तथा कुश्ती प्रतियोगिता के अंतर्गत 40-50 किग्रा., 61-70 किग्रा. तथा 40 किग्रा. वर्ग में बालोद को प्रथम स्थान तथा 51-60 किग्रा. एवं 70 किग्रा. वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा खो-खो और 100 मीटर दौड़ में बालोद को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है।

जैविक प्रमाणीकरण के लिये छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट संचालित

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट कृषि उत्पादों, लघु वनोपज उत्पादों एवं प्रस्कृत उत्पादों इत्यादि के जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त सीजीसर्ट वनों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में भी अग्रसर हो रही है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सीजीसर्ट व्ही. श्रीनिवास राव ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण समिति, भारत वानिकी एवं कृषि-सीजीसर्ट, छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन संचालित है।
- सीजीसर्ट राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार जैविक उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु प्रत्यायित संस्था है।
- छत्तीसगढ़ में इसका कार्यालय छत्तीसगढ़ विधानसभा के पास राज्य वन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर परिसर में स्थित है।
- जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में प्रमाणीकरण संस्था जैसे कि सीजीसर्ट जैविक उत्पादन, प्रसंस्करण, विक्रय अथवा हैंडलिंग क्रियाकलापों का जैविक मानक के अनुपालन अनुसार निगरानी करती है।
- गौरतलब है कि देश में जैविक खेती एवं जैविक उत्पादों की अपार संभावना को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम मानक को वर्ष 2005 में लॉन्च किया गया।
- इसके लिये एपिड़ा, नई दिल्ली ने महत्त्वपूर्ण भमिका निभाते हुए सभी प्रदेश स्तर पर प्रमाणीकरण संस्थाओं का गठन किया है। भारतीय जैविक मानक यूरोपीय मानकों और स्विट्जरलैंड के मानकों के समकक्ष है। इसी प्रक्रिया में सीजीसर्ट को जैविक प्रमाणीकरण कार्य हेतु मान्यता प्रदान किया गया है।
- सीजीसर्ट किसानों के जैविक खेतों के निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण प्रक्रिया में विभिन्न फसलों के जैविक उत्पादन में प्रबंधित फसलों के रख रखाव इत्यादि का एन.पी.ओ.पी मानक अनुसार निरीक्षण का कार्य करती है।
- प्रमाणीकरण प्रक्रिया अंतर्गत कोई भी व्यक्तिगत किसान, किसानों का समूह, प्रसंस्करणकर्त्ता, विक्रयकर्त्ता को पंजीयन कराना अनिवार्य होता है।
- सीजीसर्ट ऐसे उत्पादक कृषक समूहों का भी जैविक प्रमाणीकरण का कार्य करती है जो एक क्लस्टर में समूह बनाकर जैविक खेती का कार्य करते हैं। समूह खेती में छोटे-छोटे कृषकों द्वारा जैविक खेती करने के जैविक उत्पादन का रकबा तथा मात्रा दोनों में ही वृद्धि होती है तथा प्रमाणीकरण का खर्च भी कम पड़ता है। इसके अतिरिकत उत्पादन अधिक होने के कारण जैविक उत्पादों के व्यापारी इन उत्पादों को विक्रय के लिये आकर्षित होते हैं।

नोट :

- सीजीसर्ट वनों से संगृहित की जाने वाली लघु वनोपजों जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय उत्पाद जैसे हर्रा, बहेड़ा, आँवला, महुआ, इमली, चिरौंजी तथा वन्य शहद के प्रमाणीकरण का कार्य करती है।
- जंगलों से प्राप्त होने वाले उत्पादों की प्रकृति स्वत: ही जैविक होती है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया में इन लघु वनोपजों के उत्पादन क्षेत्रों एवं रखरखाव इत्यादि का निरीक्षण एवं मूल्यांकन का कार्य एन.पी.ओ.पी. मानक अनुसार किया जाता है।
- सीजीसर्ट द्वारा प्रसंस्करण ईकाइयों में तैयार किये जाने वाले प्रसंस्कृत जैविक उत्पादों एवं कृषि कार्यों हेतु आवश्यक जैविक खाद इत्यादि का भी प्रमाणीकरण किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने ईटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने एक दिवसीय बीजापुर प्रवास के दौरान ईटपाल स्थित बीजापुर गवर्नमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया, साथ ही उन्होंने फैक्ट्री से हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिये तैयार उत्पादों की पहली खेप को रवाना किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- बीजापुर ज़िले में निवासरत ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि एवं वन आधारित (उत्पाद) हैं तथा ज़िले में उद्योग नहीं होने के कारण ग्रामीणों के अन्य राज्यों में रोज़गार के लिये पलायन को देखते हुए ज़िला प्रशासन बीजापुर द्वारा स्थिर आजीविका एवं महिला सशक्तीरण के लिये व्यवसायिक मॉडल के रूप में गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है।
- यह ज़िला प्रशासन द्वारा कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को रोज़गार प्रदान करने के व्यवसायिक मॉडल का एक उदाहरण है, जिसमें गारमेंट आधारित उद्योग ही कम समय, कम लागत में स्थापित कर ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को रोज़गार दिया जा सकता है।
- गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना के लिये देश के बड़े गारमेंट ब्रांड मिंत्रा, मैक्स, डिक्सी इत्यादि कंपनियों से चर्चा की गई है, जिसमें डिक्सी एवं मिंत्रा कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ज़िले का भ्रमण किया गया और फैक्ट्री स्थापना पर सहमति बनी। इस प्रकार गारमेंट फैक्ट्री को 6 करोड़ 90 लाख 27 हज़ार रुपए की लागत से बनाया गया है।

नोट :

- गारमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिये 800 महिलाओं की काउंसलिंग कर 200 हितग्राहियों को प्रशिक्षण देने का कार्य प्रारंभ दिया किया। जून 2023 में डिक्सी कंपनी के साथ 05 वर्षों का अनुबंध कर 70 महिलाओं के साथ ज़िला परियोजना लाईवलीहुड कॉलेज में बनियान प्रोडक्शन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर प्रवास के दौरान कलेक्टर कार्यालय परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा लगाई जा रही है ताकि लोगों में अपनी संस्कृति को लेकर चेतना जागृत की जा सके।

मुख्यमंत्री ने इंडोर स्टेडियम, बीपीओ सेंटर और तारामंडल का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत खुर्सीपार में नवनिर्मित मिनी इंडोर स्टेडियम एवं नवनिर्मित बीपीओ सेंटर तथा नेहरू नगर में नवनिर्मित तारामंडल का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 3 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मिनी इंडोर स्टेडियम में बैडमिटन कोर्ट, 2 नग वुडन फ्लोरिंग, टेबल टेनिस के तीन कोर्ट, कैरम रूम, 3 बोर्ड शतरंज और एक हाल बनाया गया है। इंडोर स्टेडियम से अब खिलाड़ियों को खेलने की बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
- 7 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित बीपीओ सेंटर के माध्यम से लगभग 700 युवाओं को रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा।
- 2 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू नगर में नवनिर्मित तारामंडल शहरवासियों को ब्रम्हांड से परिचित कराएगा।

38वें चक्रधर समारोह का हुआ गरिमामयी शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को संगीत, नृत्य और साहित्य के लिये पूरे भारत में विख्यात छत्तीसगढ़ के रायगढ़ ज़िले के नगर निगम ऑडिटोरियम में रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक व धरमजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने दीप प्रज्ज्वलित कर 38वें चक्रधर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि 38वें चक्रधर समारोह का 19 से 21 सितंबर तक नगर निगम ऑडिटोरियम रायगढ़ में गरिमापूर्ण आयोजन हो रहा है।
- समारोह के शुभारंभ अवसर पर रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त चक्रधर समारोह के आयोजन के माध्यम से कला के विविध रूपों से रूबरू होने का मौका दर्शकों को मिलेगा।
- धरमजयगढ़ विधायक लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि रायगढ़ सुर ताल की नगरी है और चक्रधर समारोह ने राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पाई है। इसके आयोजन से कलाकारों की प्रतिभा से परिचित होने का अवसर मिलेगा।
- रायगढ़ कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने इस मौके पर कहा कि राजा चक्रधर सिंह स्वयं एक उम्दा कलाकार थे साथ ही कलाकारों के उदार संरक्षक थे। रायगढ़ कला मर्मग्यों की नगरी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर यहाँ रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली।
- चक्रधर समारोह में पहली बार ज़िले और प्रदेश की सांस्कृतिक प्रतिभाओं को मंच प्रदान किया जा रहा है, जहाँ गायन-वादन और नृत्य के कलाकारों के साथ ही युवा पीढ़ी के प्रतिभाशाली स्थानीय कलाकार भी समारोह में हिस्सा ले रहें हैं।
- चक्रधर समारोह में इस वर्ष युवा सहभागिता के तहत बड़ी संख्या में रायगढ़ ज़िले के स्कूली छात्र-छात्राओं की सामूहिक नृत्य प्रस्तुति और स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है।
- लंबे समय तक एशिया के एक मात्र संगीत विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ के 60 कलाकारों का दल भी चक्रधर समारोह में प्रस्तुति देगा।
- दल द्वारा शास्त्रीय गायन, सरोद वादन, ताल वादन, ताल कचहरी, सुगम संगीत, कथक एवं छत्तीसगढ़ के लोक गीतों एवं नृत्यों में श्रीराम को किन-किन रूपों में देखा गया है, पर आधारित (लोक में राम) की छत्तीसगढ़ी लोक संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी।
- चक्रधर समारोह का अपना ऐतिहासिक महत्त्व भी है। आज़ादी के पहले रायगढ़ एक स्वतंत्र रियासत थी, जहाँ सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियों का फैलाव बड़े पैमाने पर था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ कुमार गंधर्व और हिन्दी के पहले छायावादी कवि मधुकर पांडेय रायगढ़ से ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से जब रियासतों के भारत में विलीनीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो रायगढ़ के राजा चक्रधर विलीनीकरण के सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजा थे।
- राजा चक्रधर एक कुशल तबलावादक एवं संगीत व नृत्य में भी निपुण थे। उनके प्रयासों और प्रोत्साहन के फलस्वरूप ही यहाँ संगीत तथा नृत्य की नई शैली विकसित हुई।
- स्वतंत्रता पूर्व से ही गणेशोत्सव के समय यहाँ सांस्कृतिक आयोजन की एक समृद्ध परंपरा विकसित हुई, जिसने धीरे-धीरे एक बड़े आयोजन का रूप ले लिया। यह आयोजन इतना वृहद था कि राजा चक्रधर के देहावसान के बाद उनकी याद में 'चक्रधर समारोह' के नाम से यहाँ के संस्कृतिकर्मियों तथा कलासाधकों ने वर्ष 1985 से दस दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत की।

नोट :

मुख्यमंत्री 'मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस' में हुए शामिल

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी रायपुर स्थित निजी होटल में टाईम्स ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'मिरर नॉउ समिट-छत्तीसगढ़ पाथ टू प्रोग्रेस'में शामिल हुए और छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं सकारात्मक परिणामों पर अपनी बातें रखीं।

प्रमुख बिंदु

- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश की आधी-से-अधिक आबादी किसान है और छत्तीसगढ़ में 75 फीसदी से अधिक लोग खेती-किसानी से जुड़े हैं। हमने किसानी को फायदे का व्यवसाय बनाया और उन्हें उपज का सही दाम देने का काम किया है।
- उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता न केवल कृषि केंद्रित रही, बल्कि इसके समानांतर हमने वनांचल में रहने वाले लोगों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में प्रभावी काम किया है।
- मुख्यमंत्री बघेल ने 'गोधन न्याय योजना'से किसानों व पशुपालकों के जीवन में आए बदलावों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इसे लागू करने से पहले शासन स्तर पर लंबा अध्ययन किया गया और उसके बाद ही लोगों को इससे जोड़ा गया।
- अब तक 265 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी और लगभग 300 करोड़ रुपए का वर्मीकम्पोस्ट तैयार हो चुका है। साथ ही 10 हज़ार 200 गोठानों में से 6500 गोठान स्वावलंबी हो चुके हैं।
- उन्होंने कहा कि गोठान में आजीविका के लिये बहुत सारी एलाइड गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं और 13 हज़ार से अधिक स्व-सहायता समूहों की 2 लाख से अधिक महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों का दायरा घटा है और इन इलाकों में विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया गया है। अब वनांचलों में 67 प्रकार की वनोपज की खरीदी की जा रही है। वन उत्पादों के वैल्यू एडिशन से मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है। देश का सबसे बड़ा मिलेट प्लांट छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया है और समर्थन मूल्य में इसकी भी खरीदी की जा रही है।

नोट :

यूनिसेफ ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सराहा

चर्चा में क्यों ?

- 19 सितंबर, 2023 को यूनिसेफ इंडिया सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधियों ने कोंडागाँव ज़िले का दौरा किया एवं ज़िले में नवाचार के रूप में मानसिक स्वास्थ्य एवं कुपोषण से लड़ने के लिये तैयार की गई योजनाओं की प्रशंसा की।

प्रमुख बिंदु

- यूनिसेफ इंडिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी लुइजी डैक्विनो सहित यूनिसेफ के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय संगठन के प्रतिनिधि पश्चिम अफ्रीका के रेने एहोनु एक्पिनी, बेल्जियम के गुंटर बूसरी, चोल थाबो आयुल, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ प्रमुख जॉब जैकारीया, यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विशेषज्ञ गजेंद्र सिंह के द्वारा कोंडागाँव में संचालित यूनिसेफ के कार्यक्रमों का अवलोकन किया गया।
- दल द्वारा विशेषतौर पर 'मया मंडई', 'एनिमिया मुक्त कोंडागाँव'अभियान एवं 'युवोदय कोंडानार चैंप्स'जैसे कार्यक्रमों की प्रशंसा की गई। साथ ही स्वयं सेवकों के योगदान को सराहा गया।
- इस अवसर पर यूनिसेफ के दल द्वारा केशकाल विकासखंड के अंतर्गत बांधापारा और नाकापारा आंगनबाड़ी केंद्र में ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता 'मया मंडई', पोषण दिवस और एनिमिया मुक्त कोंडागाँव के बारे में युवाओं एवं ग्रामीणों के संग चर्चा की गई।
- उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं, मितानिन और एएनएम से टीकाकरण, एनीमिया मुक्त कोंडागाँव के कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते हुए बस्तरिया हल्बी गानों की धुन पर बच्चों एवं युवोदय स्वयं सेवकों के संग नृत्य किया।
- इस दौरान उन्होंने योजनाओं के ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन के बारे में जाना। साथ ही स्कूलों में स्वयंसेवकों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य के बारे में फैलाई जा रही जागरूकता और समुदाय में उनके योगदान पर चर्चा की।

छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) लगातार तीसरी बार पुरस्कृत

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये स्टार परफॉर्मेंस अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सोसाइटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स (सीम) द्वारा 8वें नेशनल एनर्जी मैनेजमेंट अवॉर्ड समारोह में यह सम्मान दिया गया।
- आलोक कटियार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा उक्त पुरस्कार को डॉ. अशोक कुमार, उप महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, (बी.ई.ई.) भारत सरकार की उपस्थिति में प्राप्त किया गया।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि लगातार 03 वर्षों (वर्ष 2020, 2021 एवं 2022) से क्रेडा को सीम द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य नामित एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- 'छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा)' द्वारा विगत 11 वर्षों में प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की गई हैं।
- ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 44 औद्योगिक संस्थानों द्वारा प्रदेश में लगभग 2.198 मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्वीवेलेंट (MTO) ऊर्जा की बचत कर लगभग 6.67 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन कम किया गया है।
- इस परियोजना के तहत प्रदेश के उद्योगों को कुल दस लाख से भी अधिक एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। व्यावसायिक भवन क्षेत्र में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अधिसूचित किया गया है तथा राज्य में कुल 15 भवनों को ग्रीन भवन के रूप में प्रमाणित किया गया है तथा 8 शासकीय भवनों को स्टार रेटिंग नामित करने हेतु प्रस्ताव केंद्र शासन को अग्रेषित किया गया है।
- आवासीय भवनों में ईको निवास संहिता (ECO NIWAS Samhita) के अंतर्गत ऊर्जा दक्ष भवन निर्माण तकनीक अपनाने हेतु प्रदेश के आवासीय परियोजनाओं के ऊर्जा दक्ष बनाने हेतु सतत् कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में क्रेडा द्वारा 150 से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट हेतु आयोजित किये गए हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र में ऊर्जा दक्ष उपकरणों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कुल 77 ग्रामों को मॉडल ऊर्जा दक्ष ग्रामों में विकसित किया गया है। इसी तरह 56 स्वास्थ्य केंद्रों को मॉडल ऊर्जा दक्ष स्वास्थ्य केंद्र एवं 376 शासकीय स्कूलों को मॉडल ऊर्जा दक्ष शासकीय स्कूलों के रूप में विकसित किया गया है।
- स्कूली छात्र छात्राओं को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से क्रेडा द्वारा कुल 603 स्कूलों में ऊर्जा क्लब का गठन किया गया है तथा आगामी वर्ष में 1 हज़ार से भी अधिक शैक्षणिक संस्थानों में ऊर्जा क्लब गठन किये जाने का लक्ष्य है।

छत्तीसगढ़ की चॉक परियोजना को विश्व बैंक एवं भारत सरकार से मंज़ूरी मिली

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ राज्य में स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए तेजी से बदलाव लाने की दृष्टि से स्कूली शिक्षा में सुधार हेतु चॉक (CHALK) परियोजना की विश्व बैंक एवं भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हो गई है, आज इस परियोजना के दस्तावेज़ों पर विश्व बैंक, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिकृत रूप से हस्ताक्षर किये गए।

नोट :

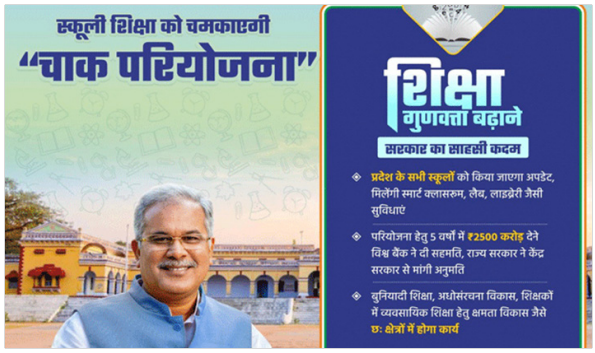

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक की मदद से शिक्षा गुणवत्ता सुधार के साथ स्कूलों का कायाकल्प किये जाने का निर्णय लिया गया है, इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पहले चरण में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- इस परियोजना के माध्यम से अगले 5 वर्षों में (जुलाई, 2023 से सितंबर, 2028) विश्व बैंक द्वारा कुल 300 मिलियन डॉलर (लगभग 2500 करोड़ रुपए) की सहायता प्राप्त होगी।
- इस परियोजना के माध्यम से प्रमुख रूप से बच्चों की उपलब्धि में सुधार की दिशा में विभिन्न कार्य पालकों की मांग के आधार पर स्वामी आत्मानंद की तर्ज पर उत्कृष्ट परिणाम देने वाले नए स्कूलों का प्रारंभ, राज्य में सुदूर अंचलों में संचालित स्कूलों की अधोसंरचना में सुधार हेतु आवश्यक समर्थन आदि कार्य किये जा सकेंगे।
- इस परियोजना के आने से छत्तीसगढ़ राज्य में विगत चार वर्षों में शुरू किये गए विभिन्न सुधार कार्यों को गति एवं विस्तार देने में आसानी हो सकेगी एवं स्कूली शिक्षा की गुणवता में व्यापक सुधार हो सकेगा।
- इस परियोजना के अंतर्गत कक्षा के स्तर अनुरूप सीखने-सिखाने से संबंधित प्रशिक्षण, शिक्षकों को अपने लिये उपयुक्त प्रशिक्षण के चयन का अवसर (ऑन डिमॉड ट्रेनिंग), उच्च प्राथमिक से लेकर हायर सेकंडरी स्तर की कक्षाओं के लिये प्रत्येक विषय एवं अवधारणा के लिये उपचारात्मक शिक्षण, स्कूलों में प्रभावी आकलन हेतु डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बच्चों के परिणामों के विश्लेषण की व्यवस्था, उच्च क्वालिटी के टेस्ट आइटम आईसीटी एवं विज्ञान प्रयोगशाला, स्मार्ट क्लासरूम की उपलब्धता, चयनित स्कूलों को अधोसंरचना विकास का लाभ, अधिक संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति बसाहट वाले विकासखंडों में स्कूल खोले जाने का प्रस्ताव जैसे कार्यों पर फोकस किया जाएगा।
- साथ ही स्कूल शिक्षा में बदलाव लाए जाने हेतु राज्य में कार्यरत स्कूल प्राचार्यों को अकादमिक एवं प्रशासनिक लीडरशिप के अलावा अन्य उपयोगी मुद्दों पर उन्हें प्रशिक्षित कर व्यवहार परिवर्तन हेतु सीमेट के माध्यम से विभिन्न क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा ज़िले के छिंदगढ़ में सुकमा ज़िले के 681 प्राथमिक शालाओं में मुख्यमंत्री स्वल्पाहार योजना का प्रारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को टिफिन का वितरण किया।
- इस योजना के तहत कक्षा पहली से पाँचवी तक के बच्चों को सप्ताह के पाँच दिन अलग-अलग मैन्यू के तहत स्वल्पाहार दिया जाएगा। जैसे सोमवार को पोहा, मंगलवार को दलिया, बुधवार को चना फ्राई, गुरुवार को मूंगदाल और शुक्रवार को वेज पुलाव दिया जाएगा।
- इससे सुकमा ज़िले के लगभग 17 हज़ार बच्चे लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत स्कूल के रसोइयों को 800 रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जाएगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित अत्याधुनिक सेंट्रल लाईब्रेरी (ग्रंथालय) का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोंडागाँव प्रवास के दौरान शासकीय गुंडाधुर महाविद्यालय परिसर में 6 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्वसुविधायुक्त अत्याधुनिक सेंट्रल लाईब्रेरी का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह लाइब्रेरी ज़िले के युवाओं के ज्ञान को बढ़ाने और कौशल विकास में सहायक साबित होगी, जिससे युवा अपने भविष्य को संवार सकेंगे।
- विदित है कि कोंडागाँव ज़िले को एक एजुकेशन हब बनाने के लिये इस केंद्रीय ग्रंथालय का शुभारंभ किया गया है। यह ग्रंथालय सभी आयु वर्ग के बच्चों, युवाओं व वरिष्ठ-जनों के लिये समर्पित होगी।
- इस ग्रंथालय को सुविधा की दृष्टि से न्यूज़ पेपर, मैगजीन जोन, किड्स जोन, डिस्कशन जोन, रीडिंग जोन में बांटा गया है ताकि पढ़ने-समझने के सभी पहलुओं को कवर कर सकें।
- इस लाइब्रेरी के साथ-साथ ई-ज्ञान पोर्टल का भी लोकार्पण किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से 128 सरकारी माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय के पुस्तकालयों में उपलब्ध सभी पुस्तकों का एक डेटाबेस बनाया गया है, और उसे ऑनलाइन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- इस पोर्टल के माध्यम से ज़िले का कोई भी विद्यार्थी या आम नागरिक, जिन्हें किसी भी किताब की जरूरत है, वह घर बैठे-बैठे ज़िले की 128 लाइब्रेरी में उपलब्ध किसी भी किताब को आवंटित करवा सकता है और उसे वह किताब खंड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से 7 दिन के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा।
- इसके साथ ही ज़िले में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु इंक्यूबेशन एवं इनोवेशन हब कोंडागाँव का उद्घाटन किया गया। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवाओं और स्टार्टअप्स की इच्छा रखने वाले लोगों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है।
- इस हेतु आज राज्य के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी भिलाई, ट्रिपल आईटी, नया रायपुर और हेडस्टार्ट के साथ एमओयू में हस्ताक्षर किये गए। ये संस्थान इनक्यूबेटर में दाखिल फाउंडर्स को व्यापार संचालन में आने वाले विभिन्न आवश्यक बिंदुओं पर मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

आयुष्मान भारत योजना में छत्तीसगढ़ को मिले तीन पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन-2023 कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिये छत्तीसगढ़ को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने कार्यक्रम में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया।
- संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ एवं स्टेट नोडल एजेंसी के सीईओ जयप्रकाश मौर्य ने नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में प्रदेश की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किये।

नोट :

- छत्तीसगढ़ को यह तीनों राष्ट्रीय पुरस्कार बड़े राज्यों की श्रेणी में आयुष्मान भारत योजना के तहत सेवाएँ प्रदान करने में लैंगिक समानता, राज्य को आवंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग और राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक परिवारों में कम-से-कम एक आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये दिये गए हैं।
- गौरतलब है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत मरीज़ों को डिजिटल कार्ड के द्वारा सुविधा एवं डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के लिये एम्स रायपुर को भी कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। डिजिटल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आभा आईडी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे मरीज़ों को ओपीडी में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में सुविधा हो रही है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में बीते 5 सालों में आम जनता को सहजता से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ करने के लिये अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की गईं, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है।
  - 'मुख्यमंत्री हाट-बाज़ार क्लीनिक योजना' के माध्यम से राज्य के सुदूर वनांचल इलाकों तक लोगों को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधाएँ सुलभ हुई हैं। इसके माध्यम से अब तक लगभग एक करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जाँच व उपचार के साथ-साथ उन्हें नि:शुल्क दवाएँ दी गई हैं। राज्य में 1814 हाट-बाज़ारों में नियमित रूप से मोबाइल मेडिकल यूनिट में डॉक्टरों की टीम पहुँचकर ज़रूरतमंद ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जाँच एवं इलाज कर रही हैं।
  - इसी तरह 'मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना'के माध्यम से नगरीय इलाकों में लोगों को घर में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो रही है।
  - 'दाई-दीदी क्लीनिक'छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव योजना है, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दाई-दीदी क्लीनिक में चिकित्सक से लेकर पैरामेडिकल टीम में महिलाएँ होती हैं, ताकि महिलाओं और किशोरी बालिकाओं का इलाज कराने में किसी भी तरह की झिझक न हो।
  - छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है, जहाँ गंभीर बीमारियों के इलाज के लिये सर्वाधिक 25 लाख रुपए की मदद 'मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना'के तहत दी जा रही है।
  - 'श्री धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना'के माध्यम से राज्य के लोगों को एमआरपी पर 50 से 72 प्रतिशत छूट पर गुणवत्तापूर्ण दवाईयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस योजना के चलते दवा खरीदी पर लोगों को अब तक 129 करोड़ रुपए की छूट मिली है।
  - 'डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना'के अंतर्गत 64 लाख से अधिक बीपीएल राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक तथा अन्य कार्डधारी परिवारों को 50 हज़ार रुपए तक उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
  - राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन कर 5233 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर संचालित किये जा रहे हैं, जहाँ मरीज़ों को 12 तरह की प्राथमिक सेवाएँ नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। 4 हज़ार से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में टेली मेडिसिन ई-संजीवनी सेवाएँ संचालित हैं।
  - ज़िला चिकित्सालयों में नि:शुल्क डायलिसिस सेवाएँ मरीज़ों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। ज़िला अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों में हमर लैब स्थापित होने से विभिन्नत तरह की जांच सुविधाएं मरीजों को सुलभ हुई हैं।
  - 'मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान'को बेहतर सफलता मिली है। इसके चलते बीते 5 सालों में वार्षिक परजीवी सूचकांक 2.63 से घटकर 0.94 हो गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का के उपार्जन तथा कस्टम मिलिंग की नीति का निर्धारण किया गया।
- इसके तहत भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अनुसार धान एवं मक्का का उपार्जन किया जाएगा। समर्थन मूल्य पर किसानों से खरीफ धान की नगद व लिकिंग में खरीदी 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक की जाएगी।

नोट :

- इसी प्रकार खरीफ मक्का की खरीदी 1 नवबंर, 2023 से 28 फरवरी, 2024 तक की जाएगी।
- मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप किसानों से धान की खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विंटल एवं मक्का प्रति एकड़ 10 क्विंटल लिकिंग सहित अधिकतम की जाएगी।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित को धान उपार्जन के लिये शासकीय प्रत्याभूति (राशि 14 हज़ार 700 करोड़ रुपए) की वैधता एक वर्ष बढ़ाते हुए 31 अक्तूबर, 2024 तक करने का निर्णय लिया गया।
- खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में उपार्जित धान की कस्टम मिलिंग से प्राप्त परिणामी चावल के फोर्टिफिकेशन के लिये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्या. (नेफेड) के माध्यम से फोर्टिफाईड राईस कर्नेल (एफ.आर.के.) की आपूर्ति किये जाने की सहमति प्रदान की गई।
- राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर के अंतर्गत वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित, द्वितीय श्रेणी) से वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिकी राजपत्रित प्रथम श्रेणी) के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा 5 वर्ष में 4 माह का शिथिलीकरण करने का अनुमोदन किया गया।
- राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6 क्रमांक 4 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
- ग्राम पंचायत घुमका, ज़िला- राजनांदगाँव को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- ग्राम पंचायत पोरथा, ज़िला-सक्ती को नगर पंचायत बनाए जाने हेतु निर्धारित मापदंड में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- छत्तीसगढ़ राज्य हिन्दी ग्रंथ अकादमी में सुदीप ठाकुर को संचालक (संविदा) नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।
- श्री रामेश्वर गहिरा गुरु प्राच्य संस्कृत महाविद्यालय श्री कोट, ज़िला-बलरामपुर-रामानुजगंज को छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के प्रावधान के अंतर्गत 100 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

विधानसभा उपाध्यक्ष ने अड़ेगा रीपा में प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को छत्तीसगढ़ विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने कोंडागाँव ज़िले में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना के तहत ग्राम पंचायत अड़ेगा के महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क में प्राकृतिक गोबर पेंट इकाई का शुभारंभ किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने गोबर पेंट निर्माण कर रहे महिला समूह को 01 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया।
- कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत् महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से गोबर पेंट इकाई की शुरुआत हुई है।
- उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से समूह की महिलाओं को गोबर पेंट निर्माण एवं बिक्री से भरपूर लाभ मिलेगा, साथ ही इससे होने वाली आय से महिलाएँ आर्थिक रूप से मज़बूत बनेंगी।

छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारी फिक्की अवॉर्ड से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ के तीन पुलिस अधिकारियों को स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड-2022 से सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि देश की प्रतिष्ठित फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) संस्था द्वारा विगत कई वर्षों से अच्छे कार्यों तथा बेस्ट प्रेक्टिसेस पर राज्य के पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया जाता रहा है।
- इसी कड़ी में 15 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में संस्था द्वारा राज्य के तीन पुलिस अधिकारियों आईपीएस डॉ. अभिषेक पल्लव, आईपीएस मयंक गुर्जर तथा आईपीएस पूजा अग्रवाल को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- कम्युनिटी पुलिसिंग केटेगरी में ज़िला दंतेवाड़ा में चलाए गए 'लोन वर्राटू'अभियान के लिये दंतेवाड़ा के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक पल्लव (आईपीएस), जो वर्तमान में ज़िला कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक हैं, को सम्मानित किया गया।
- 'लोन वर्राटू'अभियान का अर्थ होता है 'घर वापस आइये। यह अभियान उन नक्सलियों के लिये चलाया गया, जो लाल आतंक का रास्ता छोड़कर वापस समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का इरादा रखते थे। इस अभियान के तहत कई नक्सलियों ने आतंक का रास्ता छोड़ा।
- सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग केटेगरी में ज़िला राजनांदगाँव में चलाए गए 'त्रिनेत्रम'अभियान के लिये तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगाँव एवं वर्तमान नगर पुलिस अधीक्षक, आज़ाद चौक, रायपुर मयंक गुर्जर (आईपीएस) को सम्मानित किया गया है।
- 'त्रिनेत्रम'अभियान सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग हेतु चलाया गया अभियान है, जिसके तहत सीसीटीवी निगरानी को राजनांदगाँव शहर में बढ़ाया गया था। इससे पुलिस को कई केसों को सुलझाने और अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिली थी।

नोट :

- वूमेन सेफ्टी केटेगरी में राज्यस्तरीय 'अभिव्यक्ति 'कार्यक्रम के लिये पूजा अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी, पुलिस मुख्यालय को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड-2022 से सम्मानित किया गया है।
- अभिव्यक्ति अभियान के ज़रिये महिलाओं को मोबाइल के माध्यम से सुरक्षा मुहैया कराने की कवायद शुरू की गई थी।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 141 करोड़ रुपए की लागत वाले प्रदेश के पहले गन्ना आधारित एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य शासन द्वारा कबीरधाम ज़िले में प्रदेश का गन्ना आधारित सबसे बड़ा और पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है। एथेनॉल प्लांट की स्थापना को लेकर भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के खाली भूखंड की 35 एकड़ भूमि में निर्माण किया गया है।
- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कृषि पर आधारित एथेनॉल प्लांट प्राथमिकता वाली योजनाओं में है। पीपीपी मॉडल से स्थापित देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के संबंध में अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एन.के.जे. बॉयोफ्यूल लिमिटेड के मध्य किया गया है।
- एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मज़बूत होगा। किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान सुनिश्चित होगा।
- भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना के एमडी भूपेंद्र ठाकुर ने बताया कि इथेनाल प्लांट हाईब्रीड टेक्नालॉजी से बनी है, जिसमें गन्ना पेराई सीज़न के दौरान सीधे गन्ने के जूस से तथा ऑफ सीज़न के दौरान मोलासीस से एथेनॉल बनाया जाएगा।
- गन्ने के रस को एथेनाल में डायवर्ट करने के कारण अधिक जूस की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति के लिये किसानों से अधिक-से-अधिक गन्ना क्रय किया जाएगा। एथेनॉल प्लांट के निर्माण से किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान समय पर सुनिश्चित हो सकेगा।
- आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिये निजी क्षेत्र की आर्थिक एवं तकनीकी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पी.पी.पी. मॉडल का चयन किया गया है।
- राज्य शासन के निर्णय के पालन में प्रथम चरण में भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में पी.पी.पी. मॉडल से एथेनॉल प्लांट की स्थापना की गई है।

नोट :

- भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में न्यूनतम 80 के.एल.पी.डी. क्षमता के एथेनॉल प्लांट की स्थापना हेतु देश का पीपीपी मॉडल से पहला उदाहरण होने के कारण निवेशक चयन के लिये प्रक्रिया के सूक्ष्म पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निविदा सफलतापूर्वक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पूर्ण की गई।

राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का गठन

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिये राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (Media Certification and Monitoring Committee) का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले की अध्यक्षता में सात सदस्यीय एमसीएमसी का गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा समिति के गठन के संबंध में जारी आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है।
- पत्र सूचना कार्यालय (PIB) रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाये, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सदस्य डॉ. सुमन गुप्ता और मंत्रालय, नवा रायपुर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक असीम कुमार थवाईत को समिति का सदस्य बनाया गया है। इनके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक और समिति द्वारा मनोनीत दक्ष प्रतिनिधि भी इसके सदस्य होंगे।
- राज्यस्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति विज्ञापनों के प्रमाणन के संबंध में ज़िला तथा अपर/संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी दोनों से प्राप्त अपील पर निर्णय लेगी। समिति ज़िलास्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील पर पेड न्यूज़ (Paid News) के सभी मामलों या स्वप्रेरणा से लिये गए मामलों की जाँच करेगी। पेड न्यूज़ के मामले सही पाए जाने पर समिति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश देगी।

कबीरधाम ज़िले के सरोधा-दादर को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा इस वर्ष छत्तीसगढ़ के कबीरधाम ज़िले के सरोधा-दादर गाँव को राष्ट्रीय स्तर पर रजत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- सरोधा दादर को देश भर के 795 पर्यटन ग्रामों की प्रतियोगिता में विभिन्न मापदंडों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में चुना गया है।
- पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली भारत मंडपम् में आयोजित समारोह में सरोधा-दादर गाँव के मंगल सिंह धुर्वे ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
- गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कबीरधाम ज़िले में पर्यटन के विकास की संभावनाओं को विस्तार देने के लिये अलग-अलग प्रयास किये जा रहे हैं। ग्रामीण पर्यटन ग्राम सरोदा-दादर के विकास के अध्ययन के लिये कलेक्टर जनमेजय महोबे, ज़िला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल द्वारा राज्य के अलग-अलग ज़िलों में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इन्फ्लूएंसर को आमंत्रित कर भ्रमण कराया गया था। साथ ही कबीरधाम ज़िले में ग्रामीण पर्यटन के विकास की संभावनाओं के अध्ययन से अवगत भी कराया गया था।
- पुरस्कार के लिये सरोधा-दादर का चयन देश भर के 31 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के 795 गाँवों में से किया गया है।

नोट :

- सरोधा-दादर को ग्रामीण पर्यटन के लिहाज से स्थानीय परिवेश और प्राकृतिक मूल्यों के साथ ही श्रेष्ठ गतिविधियों के कारण नौ विभिन्न खंडों में श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर यह पुरस्कार दिया गया। इनमें प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण, आर्थिक आत्मनिर्भरता, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सामाजिक आत्मनिर्भरता, अधोसंरचना तथा परिवहन संपर्क जैसे मापदंड शामिल थे।
- पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सरोधा-दादर की प्रविष्टि भेजने से पहले राज्य के भीतर ज़िले के अंदर ही प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें सात गाँवों को शामिल किया गया। इनमें से चौरा, डोंगरियाकला और सरोधा-दादर का चयन किया गया। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर तीन चरणों में स्पर्धा हुई।
- आवेदन पत्र के साथ ही सरोधा-दादर पर केंद्रित पॉवरपॉइंट प्रस्तुति और वीडियो भी भेजा गया। इसके अलावा इस गाँव की विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले फोटोग्राफ भी भेजे गए।
- अधिकारियों ने बताया कि सरोधा-दादर के आदिवासी परिवेश और ठेठ ग्रामीण वातावरण को सैलानियों के लिये आकर्षण का केंद्र मानते हुए इन्फ्लुएंसर मीट के अलावा, स्थानीय स्तर पर रोज़गार पैदा करने वाली पर्यटन संस्थाओं और एजेंसियों की सक्रिय भागीदारी को भी विशेष रूप से प्रचारित किया गया।
- साथ ही चिल्फी घाटी में प्रचलित हाथ से की गई कशीदाकारी और चित्रकारी का पर्याप्त प्रचार किया गया, जिसे स्पर्धा में विशेष महत्त्व मिला। इसी आधार पर सरोधा-दादर का चयन रजत वर्ग में देश के सर्वश्रेष्ठ ग्राम के रूप में संभव हुआ।
- सरोधा-दादर को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम का पुरस्कार मिलने में यह तथ्य भी विशेष प्रभावी रहा कि यहाँ सैलानियों के लिये राज्य सरकार के प्रयासों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण को विशेषरूप से रेखांकित किया गया। यहाँ पर्यटन के माध्यम से ग्रामीणों में क्षमता और ज्ञान का विकास भी किया जा रहा है।
- गौरतलब है कि ज़िला मुख्यालय कवर्धा से करीब 50 किमी. और चिल्फीघाटी से 5 किमी. दूर स्थित सरोधा-दादर पर्वतों और घाटियों के बीच समुद्र तल से करीब 3 हज़ार फीट ऊँचाई पर स्थित है। यहाँ आमतौर पर पूरे साल यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। अक्तूबर माह से उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगती है। ठंड के मौसम में यहाँ का तापमान कभी-कभी शून्य से नीचे भी चला जाता है।
- यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भी सैलानी आते हैं। खासतौर पर चिल्फीघाटी और सरोदा-दादर में प्रकृति का आनंद लेने के लिये यहाँ पर्यटकों की आवाजाही बहुत अधिक रहती है। सरोधा-दादर में प्रकृति के सुंदर नज़ारों के कारण ग्रामीण पर्यटन की बहुत अधिक संभावना है।

नोट :

- सरोधा-दादर और पीड़ाघाट के पास एक वाच-टावर भी बनाया गया है, जहाँ से सैलानी पर्वत और घाटी के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। कवर्धा ज़िले में मुख्यरूप से बैगा आदिवासी निवास करते हैं, इनकी पारंपरिक जीवन-शैली और संस्कृति सैलानियों को विशेषरूप से अपनी ओर आकर्षित करती है।
- छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में और धार्मिक महत्त्व के स्थलों को खासतौर पर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित कराया जा रहा है। इनमें ट्राइबल टूरिज्म सर्किट को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा राज्य शासन ने भी ट्राइबल टूरिज्म सर्किट को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री ने बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में बायोफ्यूल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये दुर्ग ज़िले के ग्राम गोढ़ी में स्थापित अत्याधुनिक बायो एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र का वर्चुअल रूप से लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार के सीएसआईआर और सीएसएमआरआई के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण (सीबीडीए) द्वारा इस संयंत्र की तकनीकी डिज़ाइन और ड्राईंग तैयार की गई है।
- सीबीडीए द्वारा दुर्ग ज़िले के ग्राम गोढ़ी स्थित बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स परियोजना परिसर में स्थापित 1जी बायो-एथेनॉल प्रदर्शन संयंत्र में विशुद्ध रूप से जैवईंधन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ जैसे कि जैवईंधन उत्पादन, प्रसंस्करण और रूपांतरण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में कार्य हेतु स्थापित किया गया है।
- संयंत्र में स्थानीय कच्चा माल के रूप में छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्टार्च युक्त कंपाउंड जैसे कि अधिशेष धान, अनाज, जैसे गेहूँ, चावल के खराब दाने, जो के खाने योग्य न हों, गन्ने का रस, मोलासेस, मक्का आदि का उपयोग किया जाएगा।
- गौरतलब है कि बायो-एथेनॉल संयंत्र में प्रारंभिक तौर पर मार्कफेड में उपलब्ध खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के फीड 2 श्रेणी के अधिशेष धान का क्रय कर बायो-एथेनॉल उत्पादन का प्रयोगमूलक (अनुसंधान) कार्य जारी है। बायोफ्यूल कॉम्प्लेक्स परियोजना परिसर में एक अत्याधुनिक बायो-टेक्नोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना भी की गई है।
- प्रयोगशाला में बायो-एथेनॉल का भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार गुणवत्ता परीक्षण, सह-उत्पाद का उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिये दक्षता सुधार और नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा जहाँ संभव हो पेटेंट पंजीकृत किये जाएंगे।

नोट :

मुख्यमंत्री ने किया निर्भया कमांड और कंट्रोल सेंटर का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिये निर्मित निर्भया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (जीपीएस) का वर्चुअल शुभारंभ किया।

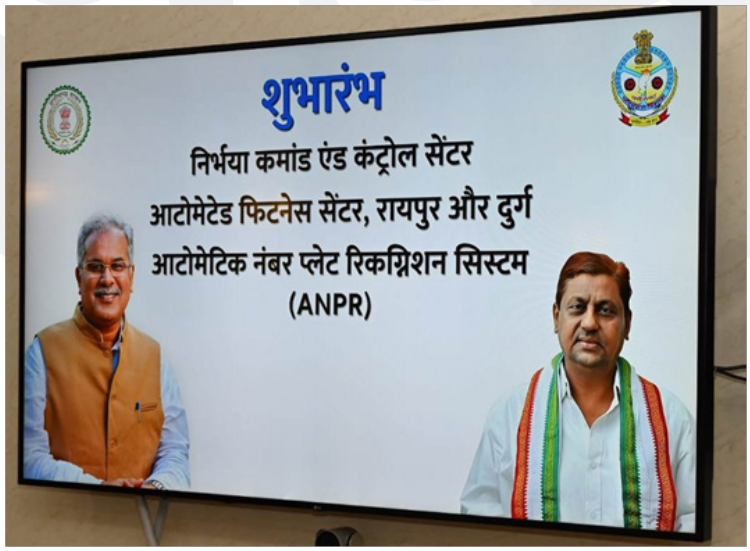

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके अलावा परिवहन विभाग की दो अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का भी वर्चुअल शुभारंभ किया, जिसमें अनफिट वाहनों से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने हेतु रायपुर व दुर्ग में ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर के साथ ही विभिन्न लिंकेज मार्गों से गुज़र रहे वाहनों की मॉनिटरिंग के लिये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा स्थापित करने से जुड़ी परियोजनाएँ शामिल हैं।
- छत्तीसगढ़ में यात्री बसों में महिलाओं एवं स्कूल बसों में विद्यार्थियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाया जाएगा और व्हीकल ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से गाड़ियों की ट्रैकिंग कि जाएगी।

नोट :

- पैनिक बटन लगने से बस में किसी प्रकार की दुर्घटना, छेड़छाड़ होने पर पैनिक बटन दबाने से तुरंत निर्भया कमांड सेंटर और पुलिस विभाग के डायल 112 को सूचना मिल जाएगी।
- इसके साथ ही बसों की लोकेशन, स्पीड आदि का भी पता चलता रहेगा। इससे बसें नियंत्रित गति से चलेंगी, जिससे हादसे की आशंका भी कम हो जाएगी। जीपीएस सिस्टम का कंट्रोल रूम डायल 112 के कार्यालय में बनाया गया है।
- इस व्यवस्था के शुरू होने से जनता को किसी तरह के खतरे तथा अनहोनी से निपटने में काफी सहूलियत होगी। वर्तमान में प्रदेश में कुल 12 हज़ार बसें संचालित हो रही हैं, जो अलग-अलग रूट से प्रदेश के कोने-कोने तक जा रही हैं। इसी तरह राज्य में लगभग 6000 स्कूल बस भी संचालित हैं। बसों में पैनिक बटन और जीपीएस के लगने से बसों की पल-पल की जानकारी मिलेगी।
- नवीन व्यवस्था के तहत स्कूल बस के रूट में भी मैप रहेगा, ताकि स्कूल बस यदि बच्चों को लेकर निर्धारित रूट के अलावा कहीं जाए तो ऑटोमेटिक अलर्ट आ जाए। इसके लिये कंट्रोल रूम में शिफ्ट के हिसाब से चार कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो लगातार सभी बस को मॉनिटर करते रहेंगे और इमरजेंसी की स्थिति में पुलिस विभाग को सूचित करेंगे।
- क्या है जीपीएस?
  - ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस एक ऐसा उपकरण है, जिसे अगर गाड़ी में फिट कर दिया जाए तो एक निर्धारित सर्वर पर गाड़ी की लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। जीपीएस सिस्टम लगने से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगेगा तथा बसों के सही रूट की जानकारी मिल सकेगी।
  - महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिये राज्य की सभी स्कूल बस और यात्री बस को पैनिक बटन सुसज्जित जीपीएस के माध्यम से मॉनिटर किया जाएगा। इसके लिये निर्भया कमांड सेंटर बनाया गया है।
- पैनिक बटन दबाते ही पुलिस को मिलेगी सूचना
  - परिवहन विभाग के आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिये परिवहन विभाग ने कई नवाचारी पहल की है। इसी कड़ी में सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिये निर्भया फंड के तहत भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश अनुसार व्हीकल ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया है।
  - परियोजना के अंतर्गत राज्य में संचालित यात्री वाहनों में जीपीएस एवं पैनिक बटन लगेगा। किसी भी आपात् स्थिति में पैनिक बटन दबाने से तत्काल ही सूचना परिवहन विभाग के कमांड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से पुलिस विभाग के डायल 112 को प्राप्त हो जाएगी, जिससे महिलाओं एवं बच्चों का यात्री वाहनों में सफर सुरक्षित होगा और आपात् स्थिति में उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।
- वाहनों की तेज़ी से होगी फिटनेस की जाँच
  - परिवहन विभाग द्वारा प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या और दुर्घटनाओं को देखते हुए रायपुर और दुर्ग में आटोमेटेड फिटनेस सेंटर की स्थापना की गई है। फिटनेस सेंटर में मेन्युअल की तुलना में अधिक वाहनों का फिटनेस टेस्ट किया जा सकता है।
  - फिटनेस सेंटर में माल वाहनों का फिटनेस टेस्ट ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा किया जाएगा और टेस्ट में फेल होने वाले वाहनों को सड़क पर नहीं चलने दिया जाएगा। सड़कों में फिट वाहनों का परिचालन हो, इसमें ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बड़ा मददगार साबित होगा और कम समय में अधिक-से-अधिक वाहनों का टेस्ट किया जा सकेगा।
  - गौरतलब है कि रायपुर और दुर्ग के बाद बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगाँव में आटोमेटिक फिटनेस सेंटर स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है।
- बिना वैध दस्तावेज़ वाले वाहनों पर होगी कार्रवाई
  - परिवहन विभाग द्वारा आज शुरू हुई तीसरी परियोजना आटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरा विथ ई-डिटेक्शन है। परियोजना अंतर्गत ऐसे वाहनों पर कार्यवाही की जाएगी, जो राजमार्ग में संचालित न होकर विभिन्न लॉकेज मार्गों से गुज़र रहे हैं।
  - इन लॉकेज मार्गों पर एएनपीआर कैमरा स्थापित किया जा रहा है, एएनपीआर कैमरे के माध्यम से प्राप्त होने वाली गाड़ियों की जानकारी को वाहन सॉफ्टवेयर के डाटाबेस से मिलान कर बिना वैध दस्तावेज़ के चलने वाली गाड़ियों पर ई-चालान किया जाएगा।
  - इस हेतु एनआईसी के सहयोग से ई-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ई-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग के टोल प्लाजा से भी जानकारी प्राप्त कर बिना वैध दस्तावेज़ के गुज़रने वाली गाड़ियों पर चालान कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

नोट :

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में नवनिर्मित 'छत्तीसगढ़ निवास' का किया वर्चुअल शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के द्वारका में नवनिर्मित 'छत्तीसगढ़ निवास' का वर्चुअल शुभारंभ कर छत्तीसगढ़वासियों को बड़ी सौगात दी।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों को नई दिल्ली में ठहरने के लिये छत्तीसगढ़ निवास के रूप में नया भवन मिल गया है। इससे प्रदेश के ज़रूरतमंदों सहित सभी के रुकने-ठहरने की दिक्कत दूर हो जाएगी।
- गौरतलब है कि नई दिल्ली द्वारका के सेक्टर 13 में बने इस नए छत्तीसगढ़ निवास भवन की कुल लागत लगभग 60 करोड़ 42 लाख रुपए है। भवन में 61 कमरे, 13 स्यूट रूम, डायनिंग हॉल एंड वेटिंग सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिये आवासीय टावर का निर्माण किया गया है।
- विभिन्न सरकारी, गैर-सरकारी कार्य एवं चिकित्सा हेतु छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाने वाले निवासियों की सुविधा हेतु इसकी परिकल्पना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी।
- विदित है कि पहले से ही छत्तीसगढ़ शासन के दो भवन 'छत्तीसगढ़ भवन'चाणक्यपुरी व 'छत्तीसगढ़ सदन'सफदरजंग हॉस्पिटल के पास नई दिल्ली में अवस्थित हैं, परंतु आधुनिक एवं छत्तीसगढ़ की बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति के लिये तीसरे भवन की ज़रूरत काफी दिनों से महसूस की जा रही थी।
- उल्लेखनीय है कि नई दिल्ली के द्वारका में नए 'छत्तीसगढ़ निवास'के निर्माण की आधारशिला 19 जून, 2020 को मुख्यमंत्री ने वर्चुअल शिलान्यास कर रखी थी। यह पहला मौका है कि जब पहली बार इस प्रकार के महत्त्वपूर्ण अत्याधुनिक भवन का निर्माण छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ से बाहर सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है।
- लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ निवास के निर्माण के लिये 43 हज़ार 803 वर्गफीट भूमि 22.50 करोड़ रुपए में क्रय की गई है। नवा छत्तीसगढ़ निवास छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपराओं की स्पष्ट झलक दे रहा है।

नोट :

- नवनिर्मित छत्तीसगढ़ निवास द्वारका के प्राइम लोकेशन में स्थित है। इसके आस-पास भव्य मॉल, फाइव स्टार होटल, खूबसूरत पार्क, नया उत्तर प्रदेश भवन, अरुणाचल भवन, दिल्ली का सबसे बड़ा इस्कॉन टेंपल आदि के अलावा कनेक्टिविटी की दृष्टि से भी इसकी लोकेशन शानदार है। द्वारका सेक्टर 13 का मेट्रो स्टेशन इस नवनिर्मित भवन के पास में ही है।

गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कोटरा और हतबंध पीएचसी तथा कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को मिला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिये कांकेर ज़िले के कोटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बलौदाबाज़ार-भाटापारा ज़िले के हतबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और महासमुंद ज़िले के कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (NQAS – National Quality Assurance Standard) प्रमाण-पत्र प्रदान किया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने विगत अगस्त और चालू सितंबर माह में इन अस्पतालों की सेवाओं का मूल्यांकन किया था। उन्होंने इस संबंध में मरीज़ों से फीडबैक भी लिया था।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम के तहत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम के मूल्यांकन में कोटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 91 प्रतिशत, कौंसरा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को 83 प्रतिशत और हतबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को 78 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं।
- राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण-पत्र प्रदान करने के पूर्व भारत सरकार के विशेषज्ञों की टीम द्वारा अस्पताल की सेवाओं और संतुष्टि स्तर का विभिन्न मानकों पर परीक्षण किया जाता है।
- इनमें उपलब्ध सेवाएँ, मरीजों के अधिकार, इनपुट, सपोर्ट सर्विसेस, क्लिनिकल सर्विसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल, गुणवत्ता प्रबंधन और आउटकम जैसे पैरामीटर शामिल हैं। इन कड़े मानकों पर खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण-पत्र जारी किये जाते हैं।

खाद्य मंत्री ने उलकिया में फूडपार्क का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर सरगुजा (अंबिकापुर) ज़िले के विकासखंड सीपापुर के ग्राम उलकिया में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने ज़िले में प्रथम फूडपार्क का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- नवीन फूडपार्क की स्थापना हेतु राज्य शासन द्वारा 6 करोड़ 27 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- खाद्य मंत्री ने कहा कि आज सीतापुर के ग्राम उलकिया में फूडपार्क की स्थापना की गई है। फूडपार्क में फूड प्रोसेसिंग उद्योग से कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण में आसानी होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।
- उन्होंने कहा कि किसी भी फूडपार्क के लिये बिजली, पानी और आवागमन की सुविधा की आवश्यकता होती है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।
- ज़िला कलेक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि इस परियोजना हेतु 8.920 हेक्टेयर क्षेत्र का आधिपत्य ज़िला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सरगुजा से सीएसआईडीसी को हस्तांतरित किया गया है।
- उक्त प्रस्तावित नवीन फूडपार्क में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिये 3000, 5000, 7500, 10000 वर्ग फीट क्षेत्रफल के लगभग 60 भूखंड प्रावधानित हैं, जिससे शासन को विभिन्न टैक्सों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति होगी। इस नवीन फूडपार्क की स्थापना होने से स्थानीय लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिलेंगे।

दृष्टि The Vision

नोट :